रांची, गुरुवार, 26 नवंबर 2026
संवत 2083, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष-2 मूल्य-2 रुपये
वर्ष-10, अंक 80 , पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

मेट्रो Rays
आगे रखने का वादा
सांध्य दैनिक



4 ▶▶ बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य की तलाश और दहेज की सौदेबाजी

बेला के किरदार में फिर दिखेंगी अनन्या पांडे ◀◀ 6

झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस 2026

एवं सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर

स्थापना दिवस परवाड़ा

15 से 28 नवम्बर, 2026



मेला-सह-प्रदर्शनी

विभागीय स्टॉल में जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं उपयोगी सेवाओं की विस्तृत जानकारी



जिला पवेलियन

हर जिले के विशिष्ट उत्पाद, पर्यटन और आर्थिक झलक साथ ही, राज्य स्तरीय मंच पर जिला स्तर के चयनित प्रतिभागियों का प्रतिभा प्रदर्शन

प्रवेश नि:शुल्क

26 से 28 नवम्बर 2026

तक खेलगांव, राँची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है



फ़ूड कोर्ट

धुस्का-घुघनी, पीठा, छिलका रोटी और असली झारखण्डी स्वाद



सांस्कृतिक संध्या

राज्य की समृद्ध कला, लोक संगीत और मनमोहक पारंपरिक नृत्यों की भव्य प्रस्तुतियाँ

जन-जन की भागीदारी
झारखण्ड की खुशहाली

उद्घाटन समारोह

गरिमामयी उपस्थिति

श्री दीपक बिरुवा
माननीय मंत्री, राजस्व, भूमि सुधार विभाग एवं परिवहन विभाग

श्री संजय प्रसाद यादव
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग



दिनांक: **26 नवम्बर, 2026** | समय: **संध्या 05 बजे से**
स्थान: **खेलगांव, राँची**

आइए, हम सब मिलकर इस उत्सव के साक्षी बनें

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

PR-394556(IPRD)26-27

न्यूज IN ब्रीफ

वाणिज्य कर विभाग के 28 कर्मचारियों का तबादला हाईकोर्ट ने किया रद्द

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने वाणिज्य कर विभाग के लिपिकीय संवर्ग के 28 कर्मचारियों के तबादले का आदेश रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने 19 नवंबर 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट किया कि सामान्य तबादले की आड़ में उठाया गया यह कदम दंडात्मक प्रकृति का है, जो कानूनन टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को तत्काल और हर हाल में चार सप्ताह के भीतर उनके मूल पदस्थापन स्थल पर वापस भेजा जाए। एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों के तबादले का दिया गया था निर्देश : सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि उप सचिव, वाणिज्य कर विभाग की ओर से 9 जुलाई 2026 को जारी तबादला आदेश देखने में सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन यह मुख्य सचिव के 28 अप्रैल 2026 के पत्र और स्थापना समिति की बैठक के निर्णय पर आधारित था। उस पत्र में राज्य के विभिन्न जिलों के कार्यालयों में वेतन मद में कोषागार के माध्यम से अवैध निकासी, कर्मचारी विवरण से छेड़छाड़, फर्जी दस्तावेजों और अन्य खातों में राशि हस्तांतरण जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। इसी आधार पर तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का तबादला करने का निर्देश दिया गया था।विभाग अपनी नीति के तहत नियमानुसार तबादले के लिए स्वतंत्रः अदालत ने माना कि 28 अप्रैल 2026 के पत्र में आरोप निहित थे और स्थापना समिति ने उसी के आधार पर याचिकाकताओं के तबादले का निर्णय लिया था। पीठ ने कहा कि बिना किसी विभागीय कार्यवाही की शुरूआत किए और कदाचार के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचे बिना इस तरह का दंडात्मक तबादला कर्मचारियों के करियर पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

खेलगांव में आज से सजेगा झारखंड की संस्कृति का महाकुंभ तीन दिनों तक बिखरेगी लोककला और संगीत की छटा

27 नवंबर को सुनिधि चौहान करेंगी लाइव प्रस्तुति, 28 को पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख बांधेंगे समां, महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क

रांचीः झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2026 और हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत राजधानी के खेलगांव में गुरुवार से तीन दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज होगा। 26 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में झारखंड की समृद्ध लोककला, जनजातीय परंपराओं, पारंपरिक नृत्य-संगीत और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव में बॉलीवुड की मशहूर गायिका सुनिधि चौहान, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख और इंडियन आइडल फेम कलाकारों सहित देश और राज्य के कई चर्चित कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। खास बात यह है कि महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। पहले दिन झारखंड की पारंपरिक कलाओं और शास्त्रीय नृत्य-संगीत की प्रस्तुतियां होंगी, जबकि दूसरे दिन सुनिधि चौहान की लाइव प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रहेगी। तीसरे दिन जनजातीय संस्कृति, नागपुरी संगीत और लोककलाओं के साथ महोत्सव का समापन होगा।

बांसुरी वादन से होगी सांस्कृतिक संध्या की शुरूआतः महोत्सव का उद्घाटन 26 नवंबर की शाम पांच बजे खेलगांव में होगा। उद्घाटन समारोह में मंत्री दीपक बिरुवा, संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडेय सिंह मौजूद रहेंगे। पहले दिन की सांस्कृतिक संध्या की शुरूआत रांची के कलाकार कुश कुमार करुआ के बांसुरी वादन से होगी। इसके बाद झारखंड की प्रमुख जनजातीय और क्षेत्रीय नृत्य परंपराओं का सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मुंडारी, नागपुरी, उरांव और



संथाली नृत्य की मनमोहक झलक देखने को मिलेगी। कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी के साथ छऊ नृत्य का आकर्षणः पहले दिन शास्त्रीय नृत्य की युगलबंदी भी विशेष आकर्षण रहेगी। कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रस्तुतियां सुमेधा सेन गुप्ता, शीतल कुमार उरांव और प्रमिला कुमारी देंगी। वहीं, गुरु तपन कुमार पटनायक छऊ नृत्य के माध्यम से झारखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को मंच पर जीवंत करेंगे।

आधुनिक नागपुरी नृत्य की प्रस्तुति वर्षा लकड़ा और उनकी टीम देगी। इसके अलावा महिला बैंड की ओर से आधुनिक नागपुरी गायन एवं वादन पेश किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 'द सजनी ग्रुप' भी अपनी प्रस्तुति देगा। 27 नवंबर को सुनिधि चौहान की लाइव प्रस्तुति से सजेगी महफिलः महोत्सव का दूसरा दिन यानी 27 नवंबर संगीत प्रेमियों के लिए खास होगा। बॉलीवुड की लोकप्रिय गायिका सुनिधि चौहान अपनी शानदार लाइव प्रस्तुति से समां बांधेंगी। उनकी प्रस्तुति को लेकर दर्शकों में खास उत्साह रहने की उम्मीद है। इस दिन इंडियन आइडल फेम शगुन पाठक भी एकल गायन प्रस्तुत करेंगे।

सितार वादन, घोड़ा नृत्य और पाइका कला का दिखेगा संगमः दूसरे दिन रांची के देवप्रिय ठाकुर सितार वादन के जरिए शास्त्रीय संगीत की मधुर छटा बिखेरेंगे। सामूहिक गायन में अद्वितीय बैंड की पारोमिता चौधरी और गृहिणी समूह अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वहीं, किशोर नायक के नेतृत्व में कुंजबन दल नागपुरी नृत्य और गायन पेश करेगा। इसके अलावा विनोद महतो और उनकी टीम घोड़ा नृत्य प्रस्तुत करेगी। अशोक कच्छप पाइका नृत्य के माध्यम से झारखंड की पारंपरिक युद्धकला और लोकसंस्कृति की झलक दिखाएंगे। 28 नवंबर को मधु मंसूरी हंसमुख की प्रस्तुति होगी मुख्य आकर्षणः महोत्सव के अंतिम दिन 28 नवंबर को विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दिन इंडियन आइडल फेम अभिषेक कुमार सांवरिया और पूजा चटर्जी एकल गायन प्रस्तुत करेंगे।

पलामू में पांच अलग-अलग हादसे, दो महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत

संवाददाता

पलामू : जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान पांच अलग-अलग हादसों में दो महिलाओं समेत पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक राजद नेता और पूर्व सैनिक का बेटा भी शामिल है। लगातार हुई इन घटनाओं से जिले में शोक का माहौल है।

सड़क हादसे में पूर्व सैनिक के बेटे की मौतः पलामू के सदर थाना क्षेत्र में सिंगरा और जोड़ के बीच एनएच-139 पर हुए सड़क हादसे में पूर्व सैनिक के बेटे खुशदिल शुक्ला की मौत हो गई। बताया जाता है कि खुशदिल बाइक से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान वह दुर्घटना के शिकार हो गए। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने किया सड़क जामः बुधवार देर शाम सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया इलाके में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच-139 को करीब डेढ़ घंटे तक जाम रखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर जाम हटवाया। मृतका लातेहार जिले के मनिका की रहने वाली थी।

संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव बरामदः मेदिनीनगर के टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया में पूजा देवी नामक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। मृतका के पिता ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है।

टैंकर पलटने और बाइक दुर्घटना में भी मौतः टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं, चैनपुर थाना क्षेत्र के बोड़ी में पानी का टैंकर पलटने से पचू चौधरी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा हैदरनगर थाना क्षेत्र के बड़ंडा में बाइक दुर्घटना में राजद नेता नसीम खान की जान चली गई।

देवर ने भाभी के सिर पर टांगी से किया हमला,गंभीर

रांची : पंडरा ओपी क्षेत्र के नायक चौक में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी भाभी के सिर पर टांगी से हमला कर दिया। इस हमले में हीरा मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनके सिर पर गहरी चोट आई है और आठ टांके लगे हैं। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बीच-बचाव करने पर किया हमलाः घटना को लेकर घायल हीरा मुंडा की बेटी आरती मुंडा ने अपने चाचा दिनेश मुंडा और चाची संगीता मुंडा के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरती के अनुसार, बुधवार शाम उनकी मां हीरा मुंडा अपने बेटों अनिल और सुनील के साथ घर के पास रखी ईंटों को दूसरी जगह रख रही थीं।

स्माइल फाउंडेशन और आशीर्वाद बाय एलियाक्सिस ने 10,788 प्लंबरों को दिया प्रशिक्षण

प्रशिक्षण के बाद करीब 60 फीसदी प्लंबरों की आय, मुनाफे या सर्विस चार्ज में हुई बढ़ोतरी

रांची : स्माइल फाउंडेशन ने आशीर्वाद बाय एलियाक्सिस के सहयोग से अगस्त 2025 से सितंबर 2026 के बीच अपने 'प्लंबर साथी प्रोग्राम' के तहत 422 व्यवहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इस दौरान कुल 10,788 प्लंबरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस पहल का उद्देश्य प्लंबरों को निःशुल्क व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उनके कौशल में सुधार करना और उनकी आजीविका को बेहतर बनाना है। प्रशिक्षण के बाद किए गए सर्वेक्षण में सभी प्रतिभागियों ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके तकनीकी कौशल में सुधार हुआ है। वहीं, करीब 60 फीसदी प्रतिभागियों ने अपनी आय, मुनाफे या सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी की जानकारी दी।

इस कार्यक्रम से झारखंड के रांची जिले के टाटीसिलवाई गांव के राकेश महतो जैसे प्लंबरों की आय में भी सुधार हुआ है। प्लंबिंग तकनीक, फिटिंग और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल करने के बाद राकेश ने अपने इलाके में इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम शुरू किया। आज वह हर महीने करीब 20 हजार रुपये कमाते हैं। इससे वह अपने माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों का खर्च उठा पा रहे हैं।

इस अवसर पर स्माइल फाउंडेशन के सह-संस्थापक शांतनु मिश्रा ने कहा कि समुदायों को आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास को सुलभ बनाना जरूरी है। प्लंबर साथी प्रोग्राम के माध्यम से प्लंबरों को व्यवहारिक कौशल हासिल करने में मदद की जा रही है, ताकि उनकी रोजगार क्षमता और आय में वृद्धि हो सके।

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों से मिली प्रतिक्रिया बताती है कि कौशल विकास से आजीविका के अवसरों में किस तरह सुधार हो सकता है। प्लंबरों को सशक्त बनाने के लिए आशीर्वाद बाय एलियाक्सिस के साथ साझेदारी करना खुशी की बात है।

कार्यक्रम से जुड़े सर्वेक्षण में झारखंड और ओडिशा के प्रतिभागियों ने भी तकनीकी कौशल में सुधार की बात कही। अधिकांश प्रतिभागियों ने आय, मुनाफे और सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी की जानकारी दी। इन परिणामों से स्पष्ट है कि व्यवहारिक कौशल विकास प्लंबरों के काम की गुणवत्ता और आय में सुधार लाने के साथ उनकी आजीविका को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

झारखंड में बढ़ी कनकनी, लातेहार में 8.2 डिग्री पर पहुंचा पारा

24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री गिरा, नामकुम में 9 और कांके में 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज

संवाददाता

रांची : आसमान से बादल छंटने के साथ ही झारखंड में ठंड का असर बढ़ने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और रात के समय कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर 13.2 से 12.4 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं, अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री से घटकर 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ठंड बढ़ने के साथ ही सुबह के समय राजधानी में दृश्यता घटकर 1500 मीटर रह गई। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 8.2



डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, कई अन्य जिलों में भी रात का तापमान 10 डिग्री के आसपास या उससे नीचे पहुंच गया है।

जमशेदपुर रहा सबसे गर्मः मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के प्रमुख शहरों में जमशेदपुर सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चाईबासा में अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 13.6 डिग्री, डालटनगंज में अधिकतम 27.2 और न्यूनतम 12.8 डिग्री तथा बोकारो थर्मल में अधिकतम 25.1 और न्यूनतम 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमानः राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लातेहार में पारा सबसे कम 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। गुमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री और खूंटी व हजारीबाग में 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री, जबकि सरायकेला में 14.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

रांची के बाहरी इलाकों में अधिक ठंडः राजधानी के अलग-अलग इलाकों के तापमान में भी अंतर देखने को मिला। हिनू में अधिकतम तापमान 24.7 और न्यूनतम 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कांके में अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, नामकुम में न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के किसी भी मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई। फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। बादल छंटने और तापमान में गिरावट के कारण आने वाले दिनों में सुबह और रात के समय ठंड का असर और बढ़ सकता है।

बारात से लौट रही सवारी गाड़ी पलटी, 15 घायल

पलामूः छतरपुर-नौडीहा बाजार रोड पर बुधवार देर रात रजमनडीह मोड़ के पास शादी समारोह से लौट रही एक सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में वाहन पर सवार 15 लोग घायल हो गए। घायलों में करीब छह बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायल बिहार के गया जिले के डुमरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। शादी से लौटते समय हुआ हादसाः मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के डुमरिया निवासी धनेश्वर मांझी के बेटे की शादी बुधवार को पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र स्थित चेगौना धाम में हुई थी। शादी समारोह संपन्न होने के बाद दूल्हे पक्ष के रिश्तेदार सवारी गाड़ी से अपने घर डुमरिया लौट रहे थे। इसी दौरान छतरपुर-नौडीहा बाजार रोड पर रजमनडीह मोड़ के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

12 सप्ताह में चौकीदार के 4% आरक्षित पद भरने का हाईकोर्ट का आदेश

साहिबगंज में लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका पर आया फैसला

संवाददाता

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले में चौकीदार नियुक्ति मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 4 प्रतिशत पदों को 12 सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने यह आदेश फूलचंद मुर्मू एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। दरअसल, साहिबगंज जिले में विज्ञापन संख्या 01/2024 के तहत चौकीदार के कुल 315 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गए थे। याचिकाकर्ता निर्धारित पात्रता पूरी करते हुए चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। उन्हें प्रवेश पत्र भी जारी किया गया



था। इसके बाद उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफलता हासिल की, लेकिन इसके बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की गई।

प्रतिवादियों ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित रखी थी। इससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा और हर्ष चंद्र ने अदालत में दलील दी कि जब विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट रूप से 4 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए थे और याचिकाकताओं ने चयन प्रक्रिया की दोनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास कर ली थीं, तो उन्हें नियुक्ति से वंचित रखना उचित नहीं है।

अधिवक्ताओं ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को उचित सुविधाएं और समान अवसर उपलब्ध कराना राज्य का वैधानिक दायित्व है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के श्री खजान सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला दिया गया। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को उचित समायोजन (रीजनबल एकोमोडेशन) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की नियुक्ति और उनके शारीरिक दक्षता परीक्षण को लेकर कोई स्पष्ट नियम निर्धारित नहीं है। इसी कारण साहिबगंज के उपायुक्त ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। मार्गदर्शन मिलने तक संबंधित पदों पर नियुक्ति स्थगित रखी गई थी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि नियुक्ति वर्ष 2015 के नियमों के अनुसार होनी चाहिए और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 4 प्रतिशत पदों को 12 सप्ताह के भीतर भरने का निर्देश दिया।

पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते की जमानत पर हाईकोर्ट सख्त, सीआईडी से जवाब तलब

9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश, 16 दिसंबर को अगली सुनवाइ, जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में जेल में बंद हैं ख्यांगते

संवाददाता

रांची : जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सीआईडी को 9 दिसंबर तक याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, प्रार्थी को 14 दिसंबर तक सीआईडी के जवाब पर



प्रतिउत्तर दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। ख्यांगते की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता चंदना कुमारी ने पक्ष रखा। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान ख्यांगते की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। छापेमारी के दौरान भी उनके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई थी। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

वहीं, सीआईडी की ओर से बताया गया कि टीडीपीएल को परीक्षा आयोजन का काम सौंपने में ख्यांगते की अहम भूमिका थी। एजेंसी के अनुसार, टीडीपीएल की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी और इसकी जानकारी ख्यांगते को भी थी। इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

जांच एजेंसी ने ख्यांगते पर टीडीपीएल से कथित तौर पर दो करोड़ रुपये कमीशन लेने का आरोप भी लगाया है।

बताया गया कि परीक्षा में अनियमितता को लेकर सीआईडी ने कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया है। इसी मामले की जांच के दौरान एजेंसी ने एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई थी। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं। इस मामले में अब तक तीन दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

सीआईडी के अनुसार, जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के कथित मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान दिए गए स्वीकारोक्ति बयान में पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की भूमिका का उल्लेख किया है। उसने टीडीपीएल को परीक्षा आयोजन की एजेंसी के रूप में चयनित करने में ख्यांगते की अहम भूमिका होने की बात कही है। हालांकि, मामले में आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है।

जिला समादेष्टा कार्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, सिमडेगा

(गृह रक्षक नव नामांकन–विज्ञापन संख्या– 01/2025)

निदेशानुसार, झारखण्ड गृह रक्षावाहिनी सिमडेगा में गृह रक्षक नव–नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या– 01/2025 के अन्तर्गत अस्वीकृत एवं स्क्रूटनी REQ. आवेदन पत्र के आलोक में दावा–आपत्ति की मांग समिति द्वारा की गई। निर्धारित समय अवधि में प्राप्त दावा–आपत्ति पत्रों का स्क्रूटनी नियामानुसार पुनः स्क्रूटनी समिति द्वारा की गई। स्क्रूटनी उपरांत स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदन पत्र सिमडेगा जिला के NIC पोर्टल https://simdega.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। अस्वीकृत आवेदन पत्र के संबंध में अब किसी प्रकार का दावा–आपत्ति समिति द्वारा स्वीकार्य नही किये जायेंगे।

ह0/–
जिला समादेश्टा,
–सह–नोडल पदाधिकारी
गृहरक्षक नव–नामांकन समिति, सिमडेगा

PR 394554 Simdega(26-27) D"

मेट्रो Rays

आगे रखने का वादा

रांची, गुरुवार, 26 नवंबर 2026

संवत 2083, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष-2 मूल्य-2 रुपये

वर्ष-10, अंक 80 , पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

सांध्य दैनिक



4 ▸▸ बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य की तलाश और दहेज की सौदेबाजी

बेला के किरदार में फिर दिखेंगी अनन्या पांडे ◂◂ 6

विधानसभा का विशेष सत्र, दूसरा दिन

खनन का बोझ झारखंड उठाए और आर्थिक लाभ से रहे वंचित, यह न्यायसंगत नहीं : मुख्यमंत्री

- विधानसभा में केंद्र के खनिज कानून में संशोधन पर पुनर्विचार या वापसी का सरकारी प्रस्ताव पेश
- हर साल 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की जताई आशंका

संवाददाता



रांचीः झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन खान एवं भूतत्व विभाग के प्रभारी मंत्री सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 के खिलाफ पुनर्विचार करने अथवा इसे वापस लेने से संबंधित सरकारी प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा।

प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 17 अगस्त 2026 को इस संशोधन कानून को अधिसूचित किया है। इसके माध्यम से राज्यों के खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर, उपकर एवं सेस लगाने की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। साथ ही, पूर्व में लगाए गए ऐसे राज्य कर, उपकर और सेस की बकाया या वसूली नहीं की गई राशि के दावों को भी अमान्य कर दिया गया है।

राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने से झारखंड को प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। इससे सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

खनिज संपदा का लाभ खनन प्रभावित लोगों को भी मिलेः प्रस्ताव में झारखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य देश के सबसे समृद्ध खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है। इसके बावजूद खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विस्थापन, जमीन से बेदखली, पर्यावरणीय नुकसान और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति के लोग निवास करते हैं। खनन गतिविधियों का सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव भी इन्हीं समुदायों पर पड़ता है। ऐसे में खनिज संपदा से मिलने वाले आर्थिक लाभ का एक हिस्सा खनन प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा जनकल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव में इसे न्यायसंगत बताते हुए कहा गया है कि खनन से होने वाले नुकसान की भरपाई करना और प्रभावित समुदायों के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना जनकल्याणकारी राज्य का नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था राज्यों का अधिकारः मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया गया है। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि खनिज युक्त भूमि भी भूमि है। इसलिए संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऐसी भूमि पर कर और उपकर लगाने का अधिकार है। कर की गणना के लिए खनिज के मूल्य अथवा उत्पादन को आधार बनाया जा सकता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के इस अधिकार को संवैधानिक और संघीय ढांचे के अनुरूप माना है। इसी पृष्ठभूमि में झारखंड विधानसभा ने झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस विधेयक, 2024 पारित किया था, जिसे राज्य सरकार ने अधिनियमित किया।

सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद थी। इस राशि का उपयोग राज्य के समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में किया जाना था। लेकिन नए केंद्रीय संशोधन के बाद राज्य सरकारें केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के बिना खनिज अधिकारों अथवा खनिज युक्त भूमि पर किसी प्रकार का कर, सेस या अन्य लेवी नहीं लगा सकेंगी।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के संसाधन होंगे कमः प्रस्ताव में नए केंद्रीय कानून के चार प्रमुख प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

पहला, जिन क्षेत्रों ने खनन का सामाजिक और पर्यावरणीय बोझ उठाया है, उन्हीं क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो जाएंगे।

दूसरा, खनन के कारण विस्थापन, जमीन से बेदखली और सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव झेलने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की दिशा में राज्य सरकार के प्रयास प्रभावित होंगे। झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस अधिनियम, 2024 इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिस पर नए कानून से विराम लग गया है।

तीसरा, राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में वित्तीय कठिनाइयां आएंगी।

चौथा, देश का संघीय ढांचा प्रभावित होगा। राज्यों के लिए अपनी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

केंद्र से कानून वापस लेने की मांगः प्रस्ताव में केंद्र सरकार से माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट एक्ट, 2026 पर पुनर्विचार करने अथवा इसे वापस लेने की मांग की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे झारखंड के संवैधानिक और वित्तीय अधिकार सुरक्षित रहेंगे तथा खनन गतिविधियों से राज्य को होने वाले नुकसान की भरपाई का रास्ता बना रहेगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े विकास कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को भी पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

भीषण सड़क हादसा : ईंधन टैंकर पलटने से हुआ विस्फोट 30 की मौत, 25 से अधिक वाहनों को चपेट में लिया

एजेंसी



काहिरा : मिस्र की राजधानी काहिरा में बुधवार को भीषण सड़क हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब ईंधन से भरा एक टैंकर काहिरा रिंग रोड पर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसने आसपास से गुजर रही कारों और बाइकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 25 से अधिक वाहन जलकर राख हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटों और आसमान में उठते काले धुएं के गुबार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हादसा ग्रेटर काहिरा क्षेत्र के गीजा प्रांत के घनी आबादी वाले अल-वर्राक इलाके में अशारा टनल के ऊपर बने हाईवे पर हुआ। स्वास्थ्य मंत्री खालिद अब्देल गफ्फार के मुताबिक, तेल से भरा टैंकर पहले सड़क के डिवाइडर से टकराया और फिर बीच सड़क पर पलट गया। टैंकर के सड़क से टकराते ही उसमें विस्फोट हो गया और देखते ही देखते आग ने आसपास से गुजर रहे वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियां और बाइक आग में जलकर खाक हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के दौरान आसमान में आग का विशाल गोला दिखाई दिया और पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। सड़क पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कई वाहन चालक हॉर्न बजाते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। आग आसपास की इमारतों तक भी पहुंची, लेकिन वे इसकी चपेट में आने से बच गईं। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे की सूचना मिलते ही कई शहरों की पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, राहत एवं बचाव कार्य के लिए 39 एंबुलेंस तैनात की गईं। घायलों को जायेद स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, इमबाबा जनरल हॉस्पिटल और वार्राक सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से जले शवों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री खालिद अब्देल गफ्फार ने मृतकों की संख्या बढ़कर 30 होने की पुष्टि की है। हादसे के बाद प्रभावित इलाके में आपातकाल घोषित कर दिया गया और लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई।

ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले खाद्य पदार्थों के पैकेट पर लगेगा लाल चेतावनी निशान, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली: ज्यादा चीनी, नमक और फैट वाले खाद्य पदार्थों की पहचान अब पैकेट देखकर आसानी से की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे खाद्य उत्पादों के पैकेट पर स्पष्ट चेतावनी चिह्न लगाने का निर्देश दिया है। इसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक चीनी, नमक या फैट वाले उत्पादों पर छह कोनों वाला लाल निशान लगाना होगा। इस निशान में संबंधित पोषक तत्व का प्रतीक और उसके साथ हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाई फैट लिखा होगा, ताकि उपभोक्ता उत्पाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और पोषण संबंधी जानकारी आसानी से समझ सकें।

तिरुपति बालाजी मंदिर को आज 121 किलो सोना दान करेगा गुमनाम भक्त

160 करोड़ का मुकुट और गहने होंगे शामिल



एजेंसी

नई दिल्ली : आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में 26 नवंबर को एक ऐसा महादान होने जा रहा है, जिसकी देशभर में चर्चा है। एक गुमनाम श्रद्धालु भगवान को 121 किलो सोने के आभूषण भेंट करेगा। इनकी अनुमानित कीमत करीब 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस भेंट में भगवान के लिए सोने का भव्य मुकुट और चरणों के लिए विशेष आभूषण शामिल हैं। खास बात यह है कि इतनी बड़ी कीमत के आभूषण दान करने वाले भक्त ने अपनी पहचान गुप्त रखी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू भी इस विशेष समारोह में शामिल होंगे। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अधिकारी औपचारिक रूप से इन आभूषणों को प्राप्त करेंगे।

टीटीडी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, श्रद्धालु की ओर से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को कुल 121 किलो सोने के आभूषण समर्पित किए जाएंगे। इनकी कीमत करीब 160 करोड़ रुपये आंकी गई है। भेंट में भगवान के लिए सोने का विशेष मुकुट तैयार कराया गया है। इसके अलावा भगवान के चरणों के लिए भी खास आभूषण बनाए गए हैं, जिन्हें पद्म पादालु कहा जाता है। इस तरह यह भेंट केवल सोने का दान नहीं, बल्कि भगवान की प्रतिमा के लिए विशेष रूप से तैयार कराए गए आभूषणों का संग्रह है। दानदाता ने इतनी बड़ी भेंट देने के बावजूद अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू 26 नवंबर की सुबह अमरावती से तिरुपति के लिए रवाना होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, वह सुबह 10 बजे तिरुपति के एसवी एग्रीकल्चरल कॉलेज स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:45 बजे तिरुमला के गायत्री निलयम पहुंचेंगे। सुबह 11:10 बजे वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स के रास्ते भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। इसके बाद 121 किलो सोने के आभूषणों को मंदिर प्रशासन को सौंपने के समारोह में शामिल होंगे। तिरुमला में कार्यक्रम पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जाएंगे। वहां से लौटकर शाम करीब 4:30 बजे अमरावती पहुंचने का कार्यक्रम है।

तिरुमला का श्री वेंकटेश्वर मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नकदी, सोना और अन्य कीमती वस्तुएं दान करते हैं। ऐसे में 121 किलो सोने के आभूषणों की यह भेंट मंदिर के लिए बेहद खास मानी जा रही है। इस महादान की चर्चा इसकी 160 करोड़ रुपये की कीमत के साथ-साथ दानदाता की गुमनाम पहचान को लेकर भी हो रही है।

टाटा मैजिक और हाइवा में भीषण टक्कर, दो की मौत, चार घायल

चितरपुर काली चौक के पास सुबह तीन बजे हुआ हादसा, एक घायल की हालत गंभीर

रामगढ़ः जिले के चितरपुर काली चौक के समीप गुरुवार तड़के करीब तीन बजे टाटा मैजिक और हाइवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।



टाटा मैजिक में सवार थे छह लोग

जानकारी के अनुसार, टाटा मैजिक गोला की ओर से रामगढ़ जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे हाइवा से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मैजिक में सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वाहन में कुल छह लोग सवार थे।

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पतालः दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालकर रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि चार घायलों का इलाज शुरू किया गया। इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने हाइवा जब्त कर शुरू की जांचः मृतक गोला के रहने वाले बताए जा रहे हैं, हालांकि खबर लिखे जाने तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर रजरप्पा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना में शामिल हाइवा (जेएच 02 एर 3351) को जब्त कर लिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी पर बाबूलाल मरांडी का हमला, बोले—भूषण बाड़ा का हो नार्को टेस्ट

संवाददाता

रांचीः नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों से जुड़ी खबर उजागर करने वाले पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दिया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि यदि सरकार वास्तव में इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है, तो कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि आखिर आरोपी विधायक पर कार्रवाई करने के बजाय आदिवासी बेटी से दुष्कर्म के आरोपों से जुड़े मामले को उजागर करने वाले पत्रकार को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? उन्होंने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई पर किसी को भरोसा नहीं है। पत्रकार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी ने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

झारखंड किसी की कृपा या भीख से नहीं, पुरखों के संघर्ष और बलिदान से बना है : कल्पना सोरेन

- विधानसभा में केंद्र के रवैये पर साधा निशाना, कहा- राज्य के वित्तीय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी रहेगा संघर्ष

संवाददाता



रांचीः झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने राज्य के वित्तीय अधिकारों और केंद्र सरकार के रवैये को लेकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड किसी की कृपा या भीख में मिला हुआ राज्य नहीं है, बल्कि यह हमारे पुरखों के लंबे संघर्ष और बलिदान की देन है। केंद्र पर राज्य के अधिकार सीमित करने का आरोपः विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने देश की संघीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासी बहुल और खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके वित्तीय अधिकारों को सीमित दायरे में समेट दिया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि अपने अधिकारों को पाने के लिए झारखंड को आखिर और कितना संघर्ष करना पड़ेगा? क्या राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए केवल केंद्र सरकार के इशारों पर निर्भर रहना होगा? उन्होंने खनिज संपदा से जुड़े राज्य के वित्तीय अधिकारों में कटौती को गंभीर विषय बताया।

वीर शहीदों और झारखंड आंदोलन को किया यादः अपने संबोधन में कल्पना सोरेन ने झारखंड के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कोई साधारण भू-भाग नहीं है। यह भगवान बिरसा मुंडा, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, नीलांबर-पीतांबर, शेख भिखारी और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जैसे महान वीरों के संघर्ष और शहादत की धरती है। इन महापुरुषों के बलिदान के कारण ही आज इस क्षेत्र की स्वतंत्र और सशक्त पहचान है।

दिशोम गुरु के संघर्षों का किया विशेष उल्लेखः उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में दशकों तक चले झारखंड आंदोलन के बाद अलग राज्य का सपना साकार हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य लक्ष्य हमेशा राज्य के हक और अधिकारों की रक्षा करना रहा है।

कल्पना सोरेन ने कहा कि हमें झारखंडी होने पर गर्व है, क्योंकि इस पहचान के पीछे त्याग, संघर्ष और बलिदान का लंबा तथा गौरवशाली इतिहास छिपा है।

सुविचार

सबसे मुश्किल रास्ता वह होता है जब आपको अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वही रास्ता आपको मजबूत भी बनाता है।

विश्व पटल पर भारत की बढ़ती धमक

विश्व पटल पर भारत का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, ऐसा आस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित थिंक टैक लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स- 2026 की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में भारत को प्रमुख शक्ति का दर्जा दिया गया है। भारत को इस सूचकांक में 100 में से 40.5 अंक मिले हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.5 अधिक है। लोवी इंस्टीट्यूट (छड्ड६८ कल्ल२३३४३ी) के एशिया पावर इंडेक्स 2026 में भारत तीसरे स्थान पर है, जो अमेरिका और चीन के बाद आता है। जापान 38.6 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है जबकि रूस 32.2 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2026 में आर्थिक और घरेलू चुनौतियों के बाद भी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है। क्षेत्रीय रक्षा सहयोग, कूटनीतिक सक्रियता और सांस्कृतिक पहुँच ने भारत की स्थिति मजबूत करने में सहयोग दिया है। लोवी इंस्टीट्यूट ह्लएशिया पावर इंडेक्सह्व इस क्षेत्र में देशों की शक्ति और प्रभाव का आकलन करता है। इसमें आर्थिक क्षमता, सैन्य ताकत, लचीलापन, भविष्य के संसाधन, आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। लोवी की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच समग्र शक्ति का अंतर 2018 में इस सूचकांक की शुरूआत के बाद सबसे कम स्तर पर पहुँच गया है। चीन की कुल शक्ति अब भी भारत से करीब 80 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। भारत की सबसे मजबूत स्थिति भविष्य के संसाधनों के क्षेत्र में रही जहां उसे तीसरा स्थान मिला है इस श्रेणी में भारत को 56.2 अंक प्राप्त हुए। आर्थिक क्षमता में भी भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत के कूटनीतिक प्रभाव को उसकी प्रमुख ताकत बताया गया है इस श्रेणी में भारत को 70.3 अंक मिले हैं और यह चौथे स्थान पर है। रक्षा नेटवर्क के मामले में भारत ने दो अंकों की छलांग लगाई है और नौवें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण -पूर्व एशियाई देशों के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग और ब्रह्मोस मिसाइलों की ऐतिहासिक मांग व बिक्री को इस सुधार का प्रमुख कारण बताया गया है। आर्थिक संबंधों के मामलों में भी भारत की स्थिति बेहतर हुई है और इस श्रेणी में भारत दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंचा है। क्षेत्रीय व्यापार और निवेश संबंधों में अपेक्षाकृत स्थिरता ने इसमें योगदान दिया है। रिपोर्ट में भारत की आर्थिक स्थिति को मिला-जुला बताया गया है और आर्थिक क्षमता का स्कोर थोड़ा घटकर 26.4 अंक रह गया। रिपोर्ट में रुपए की कमजोरी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अर्थव्यवस्थाओं के आकलन की पद्धति में बदलाव का असर भारत की सापेक्ष जीडीपी स्थिति पर पड़ा। रिपोर्ट में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। संस्कृति सूचना के आदान-प्रदान और लोगों के संपर्क में सुधार हुआ है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि भारत ने क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की दिशा में प्रगति की है। वैश्विक उथल-पुथल आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे में चुनौतियों के बावजूद रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय संबंधों और भविष्य की संभावनाओं ने एशिया में भारत की स्थिति मजबूत की है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व लोकप्रिय नेता बताया गया है जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले स्थान पर कायम हैं।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में भारी पराजय के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्वर भी भारत के प्रति बदल रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ह्लडेड इकोनामीह्व कहकर भारत का मजाक बनाया था और राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने उसे लपक लिया था। अब ट्रम्प भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए अपनी फेडरल बैंक को भारत से सीखने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि भारत की ब्याज दरें बहुत कम हैं तथा जीडीपी 7 प्रतिशत है। वर्तमान में वैश्विक उथल-पुथल के भयावह दौर में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अप्रैल जून 2026 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.8 दर्ज की गई थी। 2014 के बाद भारत में हर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर उन्नति देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में वैश्विक अस्थिरता के समय में भी भारत की स्थिति बेहतर हो रही है। इस रिपोर्ट पर विपक्ष मौन है। जब विश्व के किसी कोने से भारत विरोधी कोई बयान या रिपोर्ट आ जाती है तब भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार कोसने लगता है किंतु जब भारत के पक्ष में कोई रिपोर्ट आती है तब बगलें झांकने लग जाता है।

बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य की तलाश और दहेज की सौदेबाजी

‘ यह सवाल किसी एक परिवार, जाति, वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह उस सामाजिक मानसिकता पर चोट करता है, जिसमें विवाह को धीरे-धीरे आर्थिक लेन-देन का माध्यम बना दिया गया है। विडंबना देखिए कि लड़की के माता-पिता अपनी बेटी के लिए सरकारी कर्मचारी दामाद इसलिए चाहते हैं कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसे आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और समाज में उसे सम्मान मिले। ’

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारतीय समाज में विवाह को दो व्यक्तियों के बीच जीवनभर के साथ, विश्वास और जिम्मेदारियों का संबंध माना गया है। लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में विवाह की पवित्रता पर बाजारवाद की ऐसी छाया पड़ी है कि रिश्तों का मूल्यांकन अब व्यक्ति के संस्कार, विचार, व्यवहार और मानवीय गुणों से अधिक उसकी नौकरी, वेतन, पद और आर्थिक हैसियत से होने लगा है। विवाह के लिए लड़के की तलाश करते समय लड़की पक्ष की पहली प्राथमिकताओं में सरकारी नौकरी, अच्छा वेतन, अपना मकान, जमीन-जायदाद और सामाजिक प्रतिष्ठा शामिल हो जाती हैं। सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाए तो परिवार स्वयं को भाग्यशाली समझता है। लेकिन इसी मानसिकता के भीतर एक ऐसा विरोधाभास छिपा है, जिस पर समाज खुलकर चर्चा करने से बचता है। यदि लड़की पक्ष सरकारी नौकरी वाले दामाद को प्राथमिकता देता है और लड़के वाला पक्ष बदले में ब्रेजा, ऑडी या महँगी गाड़ी की माँग रख देता है तो क्या इसे केवल उसकी व्यक्तिगत पसंद कहकर स्वीकार कर लिया जाना चाहिए? क्या विवाह वास्तव में दो परिवारों का मिलन है या योग्यताओं और संपत्तियों की नीलामी का कोई मंच?

यह सवाल किसी एक परिवार, जाति, वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह उस सामाजिक मानसिकता पर चोट करता है, जिसमें विवाह को धीरे-धीरे आर्थिक लेन-देन का माध्यम बना दिया गया है। विडंबना देखिए कि लड़की के माता-पिता अपनी बेटी के लिए सरकारी कर्मचारी दामाद इसलिए चाहते हैं कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, उसे आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और समाज में उसे सम्मान मिले। उनकी यह इच्छा अपने आप में अनुचित नहीं है। प्रत्येक माता-पिता अपनी संतान के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब इसी सुरक्षा की तलाश में वे लड़के की नौकरी को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रमाणपत्र मान लेते हैं। सरकारी नौकरी मिलते ही लड़के का सामाजिक मूल्य बढ़ जाता है और विवाह के बाजार में उसकी कथित कीमत भी निर्धारित होने लगती है।

यहीं से दहेज की मानसिकता को खाद-पानी मिलता है। लड़के के परिवार को लगता है कि उनके बेटे ने प्रतियोगी परीक्षाएँ पास की हैं, वर्षों मेहनत की है इसलिए विवाह में महँगी गाड़ी, नकदी, जमीन, फर्नीचर और अन्य सुविधाएँ माँगना उनका अधिकार है। दूसरी ओर लड़की का परिवार भी अपनी सामाजिक हैसियत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए इन माँगों को पूरा करने की कोशिश करता है। कोई ब्रेजा को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेता है तो किसी की निगाह ऑडी पर टिक जाती है। माँग पूरी न होने पर रिश्ते टूट जाते हैं और कई बार लड़की के माता-पिता अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर कर्ज तक उठा लेते हैं। सवाल यह है कि जिस सरकारी नौकरी को बेटी के सुरक्षित भविष्य की गारंटी समझा गया था, क्या उसी नौकरी के नाम पर उसके माता-पिता को आर्थिक बोझ तले दबाना उचित है?

दहेज की समस्या को केवल लड़के वालों के लालच तक सीमित करके देखने से भी सामाजिक तस्वीर अधूरी रह जाती है। लड़की पक्ष की वह मानसिकता भी आत्ममंथन की माँग करती है, जो अच्छे संस्कारों, शिक्षा, चरित्र और पारिवारिक व्यवहार की अपेक्षा सरकारी नौकरी और आर्थिक संपन्नता को सर्वोच्च स्थान देती है। जब हम स्वयं किसी व्यक्ति को उसकी नौकरी और वेतन के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, तब अनजाने में उसी व्यवस्था को मजबूत करते हैं, जिसमें विवाह के नाम पर आर्थिक अपेक्षाएँ पैदा होती हैं। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि लड़की पक्ष की प्राथमिकता के कारण लड़के वालों की दहेज माँग जायज हो जाती है। माँग करने वाला ही अपने आचरण के लिए जिम्मेदार है। किसी की पसंद या अपेक्षा दूसरे व्यक्ति के शोषण का अधिकार नहीं बन सकती। वास्तविकता यह भी है कि सरकारी नौकरी की चमक के पीछे कई बार व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को देखने की कोशिश ही नहीं की जाती। लड़का कितना जिम्मेदार है, उसका व्यवहार कैसा है, वह महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखता है, परिवार में निर्णय लेने की उसकी सोच क्या है, वह जीवनसाथी की स्वतंत्रता और आकांक्षाओं को कितना महत्व देगा, इन प्रश्नों को अक्सर गौण कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप नौकरी और वेतन देखकर किए गए विवाह बाद में मानसिक उत्पीड़न, घरेलू कलह और आर्थिक दबाव का कारण बन जाते हैं। एक लड़की को केवल इसलिए अच्छा जीवन नहीं मिल सकता कि उसका पति सरकारी कर्मचारी है। अच्छा जीवन सम्मान, समानता, संवेदनशीलता और आपसी विश्वास से बनता है।

यहाँ एक और कड़वी सच्चाई को समझना जरूरी है। विवाह के बाद यदि बहू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घर की जिम्मेदारियाँ निभाए, परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखे और हर परिस्थिति में समझौता करे तो दामाद से भी उतनी ही जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की अपेक्षा होनी चाहिए। विवाह कोई ऐसा अनुबंध नहीं है, जिसमें एक पक्ष अपनी नौकरी और पद के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त कर ले और दूसरा पक्ष अपनी आर्थिक तथा सामाजिक क्षमता से अधिक देने के लिए बाध्य हो जाए। यदि लड़की पढ़ी-लिखी है, आत्मनिर्भर है और परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान देने में सक्षम है, तो उसकी योग्यता का सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना लड़के की नौकरी का। भारतीय कानून भी इस मानसिकता को स्वीकार नहीं करता। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दहेज लेना, देना और माँगना दंडनीय अपराध है। विवाह में स्वेच्छा से दिए गए उपहारों और दबाव, शर्त अथवा माँग के तहत लिए गए दहेज के बीच स्पष्ट अंतर है। कानून का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं बल्कि समाज में ऐसी कुप्रथा को रोकना भी है। लेकिन कानून तभी प्रभावी होगा, जब परिवार स्वयं दहेज के विरुद्ध खड़े होंगे। केवल मंचों पर दहेज विरोधी भाषण देने और निजी जीवन में महँगी गाड़ियों तथा नकदी की अपेक्षा रखने से सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा। माता-पिता को भी अपनी सोच बदलनी होगी। बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद खोजने से पहले ऐसे इंसान की तलाश करनी चाहिए, जो बेटी को बराबरी का दर्जा दे सके। लड़के वालों को भी समझना होगा कि बेटे की नौकरी उसकी मेहनत का परिणाम है, कोई ऐसी व्यावसायिक पूँजी नहीं, जिसे विवाह के बाजार में बेचकर कार या संपत्ति हासिल की जाए। यदि किसी परिवार को बेटे की शादी में गाड़ी चाहिए, तो उसे अपनी कमाई से खरीदने का साहस भी रखना चाहिए।

सुरक्षित राजधानी की दिशा में दिल्ली सरकार और केंद्र के सार्थक हो रहे प्रयास

‘ दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 19,822 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। सार्वजनिक पार्कों में छह हजार से अधिक कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 1,635 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा किया गया है। इनमें 503 बड़े पार्कों में प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई है। ’

डॉ. मयंक चतुवेर्दी

राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का सवाल लंबे समय से शासन, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती रहा है। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली से अपेक्षा भी अधिक है और यहां महिलाओं के विरुद्ध होने वाला प्रत्येक अपराध राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता है। ऐसे में पिछले नौ वर्षों के दौरान यौन अपराधों, छेड़छाड़ और महिलाओं की गरिमा भंग करने से जुड़े मामलों में दर्ज गिरावट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुष्कर्म और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में 25 प्रतिशत, छेड़छाड़ में 63 प्रतिशत और महिलाओं की गरिमा भंग करने से जुड़े अपराधों में 59 प्रतिशत की कमी के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। निश्चित ही इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस बधाई के पात्र हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में तैयार की गई सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना ने इस दिशा में एक नई सक्रियता दिखाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों का महत्व इसलिए भी अधिक है कि वे एक लंबी अवधि में आए बदलाव को रेखांकित करते हैं। वर्ष 2016 में दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के 2,155 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 1,608 रह गई। इसी अवधि में छेड़छाड़ के मामले 918 से घटकर 337 और महिलाओं की गरिमा भंग करने से जुड़े अपराध 4,165 से घटकर 1,708 पर आ गए। यह बदलाव महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के विस्तार की ओर संकेत करता है। महिला सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, पीड़ितों को तत्काल सहायता तथा यौन अपराधों के प्रभावी अभियोजन के लिए तीन महीने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सार्वजनिक स्थलों की निगरानी, पुलिस गश्त, महिला सहायता केंद्रों और न्यायिक प्रक्रिया की समीक्षा को प्राथमिकता दी।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 19,822 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है, जहां सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। सार्वजनिक पार्कों में छह हजार से अधिक कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 1,635 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा किया गया है। इनमें 503 बड़े पार्कों में प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण और नियमित पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई है। 26 जनवरी 2027 तक सभी सार्वजनिक पार्कों में बाड़ और चारदीवारी की व्यवस्था पूरी करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। महिलाओं को सहजता से पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 125 पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर प्रतिदिन औसतन 308 महिलाएं शिकायत लेकर पहुंच रही हैं। यह संख्या बताती है कि महिलाओं के लिए अलग और सहज सहायता केंद्रों की उपयोगिता बढ़ रही है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और मेट्रो पुलिस थानों में चौबीसों घंटे महिला सहायता डेस्क का संचालन भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त 178 गुलाबी स्कूटरों के माध्यम से महिला पुलिसकर्मी गश्त कर रही हैं और 35 महिला-चालित पीसीआर वैन को राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। आपातकालीन सहायता प्रणाली 112 के अंतर्गत पुलिस के पहुंचने का औसत समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर आठ मिनट दो सेकंड रह जाना भी उल्लेखनीय है। आपात स्थिति में प्रत्येक मिनट का महत्व होता है। पुलिस की त्वरित पहुंच किसी संभावित अपराध को रोकने और पीड़िता को तत्काल सुरक्षा देने में निर्णायक साबित हो सकती है। महिला सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था का आधार पुलिस की मौजूदगी के साथ सामाजिक जागरूकता भी है। दिल्ली पुलिस द्वारा लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों में प्रत्येक सप्ताह लगभग 3,514 निरीक्षण और संपर्क दौरे किए जा रहे हैं। सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुंच बनाई गई है। लगभग 5.7 लाख लोगों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 3.4 लाख लोगों को बाल सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। इन पहलों का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि महिला सुरक्षा को पुलिस थानों की चारदीवारी तक सीमित रखने के बजाय शहर के सार्वजनिक जीवन से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं को सड़क, पार्क, बाजार, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना किसी भी आधुनिक राजधानी की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस दृष्टि से दिल्ली पुलिस की कार्ययोजना व्यापक प्रशासनिक सोच का परिचय देती है। ये प्रयास बताते हैं कि सुरक्षा का अर्थ किसी घटना के बाद पुलिस कार्रवाई करना भर नहीं है। समाज में ऐसा वातावरण बनाना भी जरूरी है, जहां लड़कियां और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, संकट की स्थिति में सहायता मांगने का साहस रखें और परिवार तथा समुदाय उनकी सुरक्षा में सहभागी बनें। पुरुषों और किशोरों को भी सम्मानजनक व्यवहार, सहमति और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के अभियान लगातार चलने चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में प्रभावी कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष दोषियों को समय पर सजा दिलाना है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर तक दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 1,225 मामले दर्ज हुए। इनमें 81 प्रतिशत मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए जा चुके हैं। निर्धारित दो महीने की समय-सीमा के अनुपालन का स्तर 94 प्रतिशत बताया गया है। वर्ष 2025 में ऐसे मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की दर 99 प्रतिशत रही।वर्तमान में 25 विशेष अदालतें संचालित हैं और 37 अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को मजबूत बनाने की पहल भी स्वागतयोग्य है। दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में 17.3 प्रतिशत है। इसे वर्ष 2030 तक 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस बल में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी से शिकायतकताओं के साथ संवाद, यौन अपराधों की जांच और संवेदनशील मामलों के निस्तारण में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसके लिए भर्ती के साथ प्रशिक्षण, पदोन्नति और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में भी महिलाओं को पर्याप्त अवसर देना होगा।

पहले पानी का संकट, फिर बाजार और अब कैंसर का खतरा!

डॉ. मयंक चतुवेर्दी

तपती दोपहर में रेलवे स्टेशन पर प्यास से बेहाल बच्चे के लिए जब मां 20 रुपये की पानी की बोतल खरीदती है, तो उसका भरोसा होता है कि कम से कम यह पानी तो शुद्ध होगा। वह बोतल की कीमत से अपने बच्चे की सेहत की सुरक्षा खरीद रही होती है, किंतु जब देश के प्रमुख बोतलबंद पानी ब्रांड बिसलेरी के नमूने में संभावित कैंसरकारी रसायनों की मौजूदगी का मामला सामने आता है और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) मुकदमे की मंजूरी देता है, तब सवाल एक कंपनी से आगे बढ़कर पूरे पैकेज्ड वाटर उद्योग की विश्वसनीयता पर पहुंच जाता है। आखिर जिस पानी को शुद्धता और सुरक्षा का पर्याय बनाकर बेचा गया, वही हमारी सेहत के लिए खतरा बन जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे? वस्तुतः यह घटनाक्रम बताता है कि पानी के कारोबार में ब्रांड की प्रतिष्ठा और विज्ञापनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी वास्तविक गुणवत्ता है। बोतलबंद पानी के इस विशाल बाजार की कहानी लगभग तीन दशक पुरानी है। 1990 के दशक के बाद पानी के निजीकरण और वस्तुकरण का वैश्विक विमर्श तेज हुआ। 1995 में विश्व बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष इस्माइल सेरागेल्डिन का चर्चित कथन था कि बीसवीं सदी के युद्ध तेल के लिए हुए, इक्कीसवीं सदी के युद्ध पानी के लिए होंगे। इसने पानी को भविष्य के सबसे मूल्यवान संसाधनों में स्थापित किया।भारत में जल संकट की वास्तविकता भी इस बाजार के विस्तार का आधार बनी। दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जबकि मीठे जल संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी करीब चार प्रतिशत है। भूजल का अनियंत्रित दोहन, नदियों का प्रदूषण और पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा ने सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को चुनौतीपूर्ण बनाया। इसी परिस्थिति में सार्वजनिक जल व्यवस्था की कमजोरियों के बीच निजी कंपनियों ने शुद्ध पानी का बाजार खड़ा कर दिया। आईएमएआरसी ग्रुप के अनुसार, 2026 में वैश्विक बोतलबंद पानी बाजार 311.2 अरब डॉलर का है। भारत में आईबीईएफ की मार्च 2026 की रिपोर्ट संगठित पैकेज्ड वाटर बाजार का आकार 32,040 करोड़ रुपये बताती है, जिसके 2032 तक 57,850 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। असंगठित और प्रीमियम बाजार जोड़ने पर इसका आकार लगभग 77,600 करोड़ रुपये आंका गया है, किंतु वर्तमान में पैकेज्ड वाटर उद्योग में भूजल निकासी को लेकर संसदीय समितियों और जल विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। वस्तुतः कई क्षेत्रों में औद्योगिक दोहन से स्थानीय जलस्तर प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं। प्रकृति से प्राप्त पानी को निकालकर, फिल्टर करके और प्लास्टिक की बोतल में भरकर उसी समाज को बेचना जल संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग पर सवाल खड़ा करता है। वहीं, बोतलबंद पानी की सुरक्षा का प्रश्न रासायनिक प्रदूषण तक सीमित नहीं है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में प्रति लीटर बोतलबंद पानी में औसतन लगभग 2.40 लाख प्लास्टिक कण पाए गए, जिनमें बड़ी संख्या नैनोप्लास्टिक की थी। इनके मानव शरीर पर दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है। भारत की भीषण गर्मी में खुले ट्रकों और दुकानों के बाहर धूप में रखी प्लास्टिक की बोतलों के भंडारण पर भी सवाल उठते हैं। तापमान और भंडारण की परिस्थितियां प्लास्टिक से कुछ रसायनों के पानी में पहुंचने की आशंका बढ़ा सकती हैं, इसलिए बोतलों के निर्माण, परिवहन और भंडारण के मानकों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। विडंबना यह है कि आम आदमी जिस भूजल से बचने के लिए बोतलबंद पानी खरीदता है, वह भी कई क्षेत्रों में सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्टों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे तत्वों से प्रभावित भूजल की जानकारी मिलती रही है। पंजाब के मालवा क्षेत्र में दूषित पानी और कैंसर के मामलों को लेकर लंबे समय से चिंता व्यक्त की जाती रही है। यानी एक तरफ प्रदूषित भूजल का संकट है और दूसरी तरफ बोतलबंद पानी की गुणवत्ता पर सवाल। नागरिक अपनी जेब से पैसा खर्च करने के बाद भी सुरक्षित पानी की गारंटी नहीं पा रहा। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था की गंभीर चुनौती है।

भारतीय परंपरा में कुएं, तालाब, बावड़ियां और सरोवर बनवाना पुण्य का कार्य माना गया। हमारे पूर्वज जानते थे कि पानी बनाया नहीं जा सकता, उसे संचित और संरक्षित ही किया जा सकता है। बुंदेलखंड के जखनी गांव को जल संरक्षण के माध्यम से नई पहचान दिलाने वाले पद्मश्री उमाशंकर पांडेय का सूत्र 'खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़' इसी पारंपरिक वैज्ञानिक समझ का उदाहरण है। आज आवश्यकता है कि वर्षा जल संचयन अनिवार्य हो, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाए और भूजल दोहन पर प्रभावी नियंत्रण लगे। एफएसएसएआई तथा बीआईएस को बड़े ब्रांडों से लेकर स्थानीय संयंत्रों तक नियमित गुणवत्ता जांच करनी चाहिए। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हों और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो। नागरिक भी घर से निकलते समय स्टील, तांबे या कांच की पुनः उपयोग योग्य बोतल साथ रखने की आदत अपनाएं।

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।

प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website :** www.metrorays.in

email : metrorays.ranchi@gmail.com

न्यूज IN ब्रीफ

11 लोगों को लौटाए गए चोरी व गुम हुए मोबाइल

साहिबगंज : पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ह्यखोजे मोबाइलह्ल कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिरवाबाड़ी थाना परिसर में 11 लोगों को उनके चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन वापस किए गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार के नेतृत्व में शाम चार बजे मोबाइल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस दौरान नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी शशि सिंह, बोरियो थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौहान सहित राजमहल और तालझारी थाना के पदाधिकारी उपस्थित थे। पुलिस ने तकनीकी सहायता और प्रयासों से बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस के प्रति आभार जताया थानावार बरामद मोबाइल में नगर थाना क्षेत्र के दो जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के छह, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक और बोरियो थाना क्षेत्र के दो मोबाइल शामिल हैं। इस प्रकार कुल 11 मोबाइल उनके स्वामियों को सुपुर्द किए गए ।

साहिबगंज बंदरगाह पर पहुंचा अंतरराज्यीय क्रूज जहाज सैकड़ों पर्यटकों ने लिया गंगा का नजारा



साहिबगंज : अंतरराज्यीय क्रूज जहाज साहिबगंज बंदरगाह पर पहुंचा।जहाज के बंदरगाह पर रुकने के दौरान सैकड़ों पर्यटक उससे नीचे उतरे और कुछ देर तक बंदरगाह परिसर का जायजा लिया।इस दौरान पर्यटकों ने मोबाइल फोन से तस्वीरें भी खींचीं और आसपास के नजारों का आनंद लिया।बुधवार सुबह करीब 7:15 बजे क्रूज जहाज को साहिबगंज बंदरगाह से आगे के सफर के लिए रवाना हुए पुराना जहाज घाट के समीप से गुजरते क्रूज जहाज की तस्वीर भी कैमरे में कैद की गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार यह क्रूज एमवी गंगा विलास होने की संभावना है।उपलब्ध यात्रा कार्यक्रम में कोलकाता से साहिबगंज होते हुए बटेश्वरस्थान,भागलपुर,मुंगेर और पटना की ओर जाने का मार्ग दर्ज है।भागलपुर से संबंधित 24 नवंबर की प्रकाशित खबर में भी क्रूज के कोलकाता से आने की पुष्टि की गई है।

राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में स्कूली बच्चों को भी मिलेगा काव्य पाठ का अवसर

साहिबगंज : साहित्य और कविता के प्रति स्कूली बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ह्यसाहित्य की दुनियाह्ल राष्ट्रीय साहित्यिक मंच की ओर से आगामी 9 एवं 10 जनवरी 2027 को साहिबगंज शहर के मध्य स्थित उत्सव बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।सम्मेलन में स्थानीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी अपनी काव्य प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाएगा।इसको लेकर मंच के राष्ट्रीय महासचिव सुधीर श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी,साहिबगंज को पत्र भेजकर जिले के सभी विद्यालयों को इसकी जानकारी देने का अनुरोध किया है।पत्र के अनुसार,स्कूली बच्चों के चयन के लिए 3 दिसंबर 2026 को सुबह 9 बजे राजस्थान मध्य विद्यालय में चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।इस प्रतियोगिता में चयनित छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच पर कविता पाठ करने का अवसर मिलेगा।मंच की ओर से प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम पांच विद्यार्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल कराने का आग्रह किया गया है।आयोजकों का उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी साहित्यिक एवं काव्य प्रतिभा को पहचानकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है।

महिला की मौत मालगाड़ी की चपेट में आने से होने की आशंका



साहिबगंज : फरक्का-एनटीपीसी रेलवे ट्रैक पर बुधवार को एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। इरकोन के निकट पोल संख्या 33/6 के पास दोपहर करीब 12:15 बजे महिला का शव बरामद किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला की मौत मालगाड़ी की चपेट में आने से होने की आशंका जताई जा रही है। मृतका की पहचान 52 वर्षीय कौशल्या देवी पति स्वर्गीय भुटका साह के रूप में परिजनों ने की है।घटना की सूचना मिलते ही बरहेट थाना के सहायक अवर निरीक्षक मनसा हजम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर थाना पहुंचाया।फिलहाल महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। वह रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंची और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ पुलिस इसकी जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

नशे के खिलाफ जागरूकता वाहन रवाना, गांव-गांव पहुंचाया जाएगा संदेश

रामगढ़ : झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत जिले में नशा मुक्ति को लेकर व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को उपायुक्त ऋतुराज ने जिला समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। अभियान के माध्यम से आमजनों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को बर्बाद करने के साथ-साथ पूरे परिवार एवं समाज को प्रभावित करता है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सामूहिक प्रयास और व्यापक जन-जागरूकता जरूरी है। उन्होंने लोगों से नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलखो, अभियान संस्था के झारखंड समन्वयक आकाश शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।

जाति आय और निवास प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन हो : उपयुक्त

प्रत्येक 15 दिनों में विभागीय कार्यों की समीक्षा सुनिश्चित करने पर जोर

मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज और विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि हस्तांतरण

संवाददाता

साहिबगंज : उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं, विभागीय कार्यों, लंबित प्रशासनिक मामलों एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी कार्यों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

विकास परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन प्राथमिकता

जिसमें मेडिकल कॉलेज पावर ग्रिड, साइंस कॉलेज, एकलव्य विद्यालय नगर परिषद कार्यालय श्रमिक विद्यालय श्रमिक चौक बरहरवा बस स्टैंड बरहेट प्रखंड में आपूर्ति विभाग के अनाज भंडारण गोदाम गंगा नदी थाना भवन व तीनपहाड़ थाना भवन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण एवं भूमि चिह्नित करने से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इस संबंध में उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित भूमि संबंधी प्रक्रियाओं में तेजी लाते हुए आवश्यक कार्रवाई अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनहित एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि संबंधी मामलों के कारण अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।



प्रमाण पत्र निष्पादन एवं प्रशासनिक कार्यों की नियमित समीक्षा पर जोर

जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्रों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में जाति प्रमाण पत्र के लंबित आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रमाण पत्रों के निष्पादन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन नियमित रूप से उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को प्रत्येक 15 दिनों में अपने कार्यालय के कर्मियों के साथ बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों लंबित मामलों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने तथा समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

भू-अर्जन मुआवजा भुगतान एवं विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा

भू-अर्जन से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए मुआवजा राशि प्राप्त हो चुकी है, उनसे संबंधित रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया अविलंब पूरी की जाए। सभी अंचल अधिकारी संबंधित रैयतों के आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए मुआवजा भुगतान हेतु लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करें।

स्वास्थ्य सेवाओं वं अन्य जनहितकारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश

उपायुक्त ने सदर अस्पताल साहिबगंज में खराब सीसीटीवी कैमरों की मरम्मति कराते हुए निगरानी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही सिविल सर्जन को जिले की सभी एंबुलेंस का शीघ्र मरम्मतीकरण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य एवं आपातकालीन परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।

उन्होंने जिले के सभी निजी विद्यालयों का व्यापक निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का निर्देश भी संबंधित पदाधिकारियों को दिया।उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्री सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक, आईटीडीए संजय कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल सदानंद महतो सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

मदरसा ताईदुल इस्लाम की व्यवस्था पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग

ग्रामसभा की अनदेखी कर प्रबंधन समिति गठन मध्याह्न भोजन में अनियमितता

संवाददाता

साहिबगंज : मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र के डोकाडीह मंडरो स्थित मदरसा ताईदुल इस्लाम की प्रबंधन व्यवस्था और बहाली प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।मदरसे में कथित अनियमितताओं मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी और चार पदों पर होने वाली बहाली में परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है।ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने के साथ बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।ग्रामीणों ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि ग्रामसभा की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही मदरसे की प्रबंधन समिति का गठन कर दिया गया।इसके अलावा फर्जी छात्र उपस्थिति दिखाकर मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनाज का उठाव किए जाने की भी शिकायत की गई है।ग्रामीणों ने छात्र उपस्थिति पंजी अनाज उठाव से संबंधित अभिलेखों और मध्याह्न भोजन योजना की वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है।आवेदन में यह भी कहा गया है कि प्रबंधन समिति के गठन को लेकर विवाद होने के बावजूद मदरसे में चार पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।ग्रामीणों ने प्रधान मौलवी एवं उनके सगे-संबंधियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने



की कोशिश किए जाने का आरोप लगाते हुए इसे परिवारवाद का मामला बताया है।साथ ही मामले में सांसद प्रतिनिधि की कथित भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी शिकायत की गई थी,लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।उन्होंने विभाग से कथित अवैध प्रबंधन समिति को निरस्त करने,चार पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने,छात्र उपस्थिति और मध्याह्न भोजन योजना का भौतिक सत्यापन कराने का आरोप सही पाए जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी नयन कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है।फिलहाल इस संबंध में तत्काल कुछ बताना संभव नहीं है।वहीं मदरसे के हेड मौलवी मोहम्मद सलीमुद्दीन ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया।उन्होंने कहा कि मदरसे में अब तक अपनाई गई सभी प्रक्रियाएं नियमसंगत हैं और जैक के आदेश के अनुसार ही कार्य किया गया है।हालांकि,मदरसे में कुल कितने बच्चे नामांकित हैं और प्रतिदिन कितने विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं,इस सवाल पर वे तत्काल स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके।फिलहाल मदरसे की प्रबंधन समिति,मध्याह्न भोजन योजना और बहाली प्रक्रिया को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है।अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग ग्रामीणों की शिकायत पर कब जांच शुरू करता है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।ज्ञापन सौंपने वालों में मोहम्मद मफिजुद्दीन, आबुल कासिम, मास्टर जाकिर, मोहम्मद शरीफ आलम, मोहम्मद हुर्मूज अली, मोहम्मद बहारुद्दीन अंसारी सहित कई ग्रामीण शामिल थे।

बीडीओ व सीओ ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन

सरकारी कृषि योजनाओं की भी दी गई जानकारी

संवाददाता

चंदवा : झारखंड राज्य स्थापना दिवस पखवाड़ा के अवसर पर बुधवार को चंदवा प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह कृषि मेला का आयोजन किया गया। जिला कृषि कार्यालय, लातेहार के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ चंदन प्रसाद एवं अंचलाधिकारी सुमित कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यशाला में उपस्थित किसानों को रबी फसलों की बेहतर पैदावार, आधुनिक कृषि तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की जानकारी दी गई। कृषि विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं से भी किसानों को अवगत कराया गया। अधिकारियों ने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ उन्नत तकनीकों को अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम में किसानों को खेती से जुड़ी नई जानकारियां उपलब्ध कराने के साथ कृषि क्षेत्र में बेहतर संभावनाओं के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार पाठक, विधायक प्रतिनिधि सुनील मुंडा, सभी जनसेवक एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।



जिला टास्क फोर्स खनन की बैठक में अवैध खनन भंडारण व परिवहन पर रोक लगाने का निर्देश

खनन क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण सीसीटीवी व्यवस्था दुरुस्त रखने व दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने पर जोर

संवाददाता

साहिबगंज : समहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स खनन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग उपस्थित थे। वही जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण व परिवहन पर रोक लगाने वैध खनन गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सप्ताह में कम से कम दो खनन क्षेत्र का प्रशासनिक माप कराना सुनिश्चित करेंगे। जबकि उपायुक्त ने जिले में संचालित सभी चेकनाकों का नियमित व औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।चेकनाकों पर



संधारित पंजियों सीसीटीवी कैमरों दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति वाहनों की संख्या, खनिजों के प्रकार तथा वाहनों के कागजात चालानों की जांच सुनिश्चित करने को कहा गया जब जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरा की नियमित मरम्मती कराई जाए और चालू अवस्था में रखी जाए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुमंडल में एक-एक ड्रोन एवं एक-एक ऑपरेटर प्रतिनियुक्ति किया जाए जो समय-समय निरीक्षण में साथ-साथ जाए ताकि उनके द्वारा खनन क्षेत्र का वीडियो ग्राफी व फोटोग्राफी कराया जा सके।बालू के अवैध उत्खनन भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी बालू घाटों का नियमित निरीक्षण करने अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया।इसके अतिरिक्त अवैध क्रशर, चिमनी, मिट्टी कटाव एवं बालू से संबंधित मामलों में नियमित निरीक्षण और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित गतिविधियों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया। अवैध खनन पट्टा क्षेत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक खनन करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने तथा नियमानुसार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया।उपायुक्त ने अवैध मिट्टी कटाव की आशंका को देखते हुए विशेष निगरानी रखने तथा ऐसे मामलों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया। साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, थाना प्रभारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस संदर्भ में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा नियमित निरीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कूअनुमंडल पदाधिकारी राजमहल सदानंद महतो सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे।

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए डिएंड्रा डॉटिन की वेस्टइंडीज टीम में वापसी

टी20 और वनडे सीरीज के लिए एक ही 15 सदस्यीय टीम घोषित, हेली मैथ्यूज संभालेंगी कप्तानी



नई दिल्ली। वेस्टइंडीज की अनुभवी हरफनमौला खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन पाकिस्तान के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों की टीम में लौट आई हैं। वेस्टइंडीज को इस सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने हैं। डॉटिन सितंबर में जिम्बाब्वे दौरे पर वेस्टइंडीज के पिछले अंतरराष्ट्रीय अभियान का हिस्सा नहीं थीं। उन्हें निजी कारणों से अवकाश दिया गया था।

डॉटिन को चोट के कारण सीरीज से बाहर हुईं ऑफ स्पिनर अशमिनी मुनिसार की जगह टीम में शामिल किया गया है। बाकी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वेस्टइंडीज ने दोनों प्रारूपों के लिए एक ही 15 सदस्यीय टीम चुनी है।

हेली मैथ्यूज टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि चिनेल हेनरी उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगी। इस सीरीज के साथ मैथ्यूज की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में भी वापसी होगी। जिम्बाब्वे दौरे के टी20 चरण के लिए उन्हें निजी कारणों से अवकाश दिया गया था। उनकी गैरमौजूदगी में हेनरी ने वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में 3-0 से जीत दिलाई थी। इससे पहले टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी।

इस साल की शुरूआत में टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज ने 2028 के संस्करण के लिए पहले ही अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मुकाबले आईसीसी महिला चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। यह चैंपियनशिप 2029 के वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली टीमों का निर्धारण करती है। तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले 8, 10 और 12 दिसंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद 15, 17 और 20 दिसंबर को वनडे मुकाबले होंगे। सीरीज के सभी मैच डोमिनिका के रोसेउ स्थित विंडसर पार्क में खेले जाएंगे।

पाकिस्तान सीरीज के लिए वेस्टइंडीज महिला टीम

हेली मैथ्यूज (कप्तान), चिनेल हेनरी (उपकप्तान), आलिया एलीन, एबोनी ब्रैथवेट, शेमेन कैंपबेल, जहजारा क्लैक्सटन, डिएंड्रा डॉटिन, अफी फ्लेचर, जैनिलिया ग्लासगो, रियालियाना ग्रिमंड, शॉनिशा हेक्टर, जैडा जेम्स, मैंडी मंगरू, करिश्मा रामहरैक और स्टेफनी टेलर।

अंकित सिवाच ने 'ढाई चाल' के अपने किरदार पर खोले राज, कहा- वह अपने नियम खुद बनाता है

अभिनेता अंकित सिवाच की आगामी वेब सीरीज 'ढाई चाल' जल्द रिलीज होने वाली है। सीरीज के प्रचार के दौरान अंकित ने अपने किरदार के विभिन्न पहलुओं को निभाने के अनुभव साझा किए। अंकित सिवाच ने बताया कि उनके किरदार के फैसलों के पीछे की वजह को समझना और उसके अलग-अलग पहलुओं को दिखाना उनके लिए बहुत ही मजेदार अनुभव रहा है। उन्होंने कहा, ''ढाई चाल' में मेरे लिए सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात विलेन का किरदार निभाना था। मेरा किरदार एक ऐसा इंसान है, जो बने-बनाए नियमों को मानने में यकीन नहीं रखता है, बल्कि अपने नियम खुद बनाता है और उन्हें मानता है। वो ताकत को समझता है और जानता है कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। इस शख्सियत में कई परतें हैं, जो एक एक्टर के तौर पर मेरे लिए बहुत ही मजेदार हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'एक बात जो मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं, वो ये है कि मेरा किरदार ग्रे शेड वाला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विलेन वाला है। मुझे लगता है कि हमें 'ग्रे शेड' शब्द को महिमामंडित करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे पूरी तरह से भ्रष्ट लोग हैं, जो बहुत ही क्रूर होते हैं और मेरा कैरेक्टर ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी दुनिया में सच में मौजूद हैं। रोल की मुश्किलों और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने के मौके के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'एक एक्टर के तौर पर मैं हमेशा ऐसे मौके तलाशता रहता हूं, जो मुझे पहले निभाए गए कैरेक्टर्स से आगे बढ़ने का मौका दें। इस कैरेक्टर को दिलचस्प बनाने वाली बात ये है कि वो सिर्फ एक खास खूबी से नहीं पहचाना जाता। उसका एक डार्क साइड है, लेकिन उसके दूसरे पहलू भी हैं, जो उसे इंसान बनाते हैं। इन अलग-अलग शेड्स को निभाना और ये समझना कि उसके फैसलों के पीछे क्या वजह है, ये एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव रहा है। '



महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी : भारत ने जापान को 4-0 से रौंदा, सेमीफाइनल में मलेशिया से होगा सामना

भोपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 के अपने अंतिम लीग मुकाबले में जापान को 4-0 से करारी शिकस्त दी। बुधवार को मिली इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और लीग चरण का समापन शीर्ष स्थान पर रहते हुए किया। अब सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना मलेशिया से होगा। टूर्नामेंट में अजेय रहने वाली दोनों टीमों के बीच मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल से पहले अपनी दावेदारी मजबूत की।



भारत की ओर से दीपिका ने दो गोल किए, जबकि लालरेमसियामी और नेहा ने एक-एक गोल दागा। मुख्य कोच श्योर्ड मारिन के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने सभी पांच मुकाबले जीतकर 15 अंक हासिल किए। इस जीत के साथ भारत ने 24 घंटे के भीतर अपनी ही विश्व रैंकिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। एक दिन पहले पांचवें स्थान पर पहुंची भारतीय टीम अब अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ताजा विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जो उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है।जापान के तेज दबाव के बावजूद भारत ने आत्मविश्वास के साथ मुकाबले की शुरूआत की और शुरूआती चुनौती का बेहतर जवाब दिया। तीसरे मिनट में नवनीत ने भारत के लिए पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन दीपिका का प्रयास लक्ष्य से बाहर चला गया। मुख्य कोच अकिरा ताकाहाशी के नेतृत्व में जापान ने मजबूत रक्षात्मक संरचना बनाए रखी। गोलकीपर यू कुडो ने कई शानदार बचाव किए, जबकि रीना यामामोटो ने जापान के आक्रमण में सक्रिय भूमिका निभाई। हालांकि, भारत को 12वें मिनट में पहली सफलता मिल गई। नवनीत ने आक्रमण को जारी रखा और लालरेमसियामी ने रिवर्स फ्लिक के जरिए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। बलजीत कौर ने बाईं ओर से शानदार मूवमेंट दिखाया। उन्हें मध्यपंक्ति में उतारने से भारत के आक्रमण को एक नया आयाम मिला।

आईएलटी20 : दुबई कैपिटल्स ने दर्ज की सीजन की पहली जीत डेजर्ट वाइपर्स को 45 रन से हराया

दुबई। दुबई कैपिटल्स ने डीपी वर्ल्ड आईएलटी20 के पांचवें सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। बुधवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कैपिटल्स ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए डेजर्ट वाइपर्स को 45 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबई कैपिटल्स ने सात विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स की टीम 17.5 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। दुबई कैपिटल्स की ओर से सैम बिलिंग्स ने 31 गेंदों पर 43 रन और रोवमैन पॉवेल ने 12 गेंदों पर तेजतर्रार 28 रन बनाए। गेंदबाजी में नूर अहमद ने चार विकेट लेकर सबसे अहम भूमिका निभाई। मुस्तफिजुर रहमान ने दो विकेट हासिल किए, जबकि दुश्मंथा चमीरा और हसन खान ने भी दो-दो विकेट लिए। डेजर्ट वाइपर्स की ओर से एंड्रिस गॉस ने सर्वाधिक 30 गेंदों पर 27 रन बनाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दुबई कैपिटल्स की शुरूआत अच्छी नहीं रही। मसूद गुरबाज दो गेंदों पर दो रन बनाकर फाफ डुप्लेसिस के साथ गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए। इस समय टीम का स्कोर आठ रन पर एक विकेट था। इसके बाद मैक्स होल्डन ने डुप्लेसिस के साथ मिलकर पावरप्ले तक पारी को संभाला। दोनों के बीच 34 गेंदों पर 37 रन की साझेदारी हुई।





दिसंबर में सलमान फैंस को देंगे

डबल तोहफा

'मातृभूमि' की रिलीज के बाद दिसंबर महीने में ही सलमान खान फैंस को एक और गिफ्ट देने वाले हैं. उनके बर्थडे के मौके पर 'मॉन्स्टर' से जुड़ा कुछ खास होने वाला है. सलमान खान दिसंबर के महीने में डबल धमाका करने वाले हैं. वो अपने तमाम चाहने वालों को दो-दो गिफ्ट देने वाले हैं. पहला तोहफा तो लंबे समय से अटकी पड़ी उनकी फिल्म 'मातृभूमि' है और दूसरा तोहफा उनकी अपकमिंग फिल्म 'मॉन्स्टर' से जुड़ा है. ऐसी जानकारी है कि 'मॉन्स्टर' के मेकर्स सलमान खान के बर्थडे के लिए कुछ खास प्लान कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर उनके बर्थडे पर क्या होने वाला है. चलिए सबसे पहले जानते हैं उनकी फिल्म 'मातृभूमि' के बारे में. दरअसल, ये फिल्म पहले इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी. हालांकि, रिलीज में देरी हुई. अब ये फिल्म 4 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है. 10 नवंबर को सलमान ने इस फिल्म का ट्रेलर वीडियो जारी किया. ट्रेलर के जरिए ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की गई.

'मातृभूमि' के बाद 'मॉन्स्टर' का टीजर

'मातृभूमि' की रिलीज के 23 दिनों के बाद फैंस 2027 में रिलीज होने जा रही सलमान की फिल्म 'मॉन्स्टर' की भी झलक देख पाएंगे. ये एक बड़ी फिल्म है, जिसमें नयनतारा समेत और भी कई सितारे हैं. सलमान टीम के साथ पिछले कुछ महीने से इस पिक्चर की शूटिंग में बिजी हैं. एक रिपोर्ट की मानें तो 27 दिसंबर को सलमान के 61वें बर्थडे के मौके पर इस फिल्म का टीजर जारी किया जा सकता है.

कहां 'मॉन्स्टर' की शूटिंग कर रहे सलमान ?

बता दें कि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर टाइटल भी अनाउंस नहीं किया है. हालांकि, रिपोर्ट्स में इसका नाम 'मॉन्सटर' ही बताया जा रहा है. ऐसे में हो सकता है कि मेकर्स टीजर जारी करने के साथ फिल्म के नाम का भी ऑफिशियल ऐलान करें. रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि सलमान फिलहाल पुणे में 'मॉन्स्टर' की शूटिंग कर रहे हैं. 15 नवंबर से पुणे में शूटिंग शुरू हुई है. बताया जा रहा है कि ये 10 दिनों का शेडयल है.



बेला के किरदार में फिर दिखेंगी अनन्या पांडे

मशहूर निर्देशक करण जौहर आगामी वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन की वापसी के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर सीरीज की मुख्य अभिनेत्री अनन्या पांडे का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बेला (बे) के किरदार में नजर आ रही हैं। वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, 'दिन को जी भरकर जियो, क्योंकि वह फिर से धमाका करने आ गई है। वेब सीरीज 'कॉल मी बे' का नया सीजन 17 दिसंबर से स्ट्रीम होगा।' करण जौहर ने वेब सीरीज के दूसरे सीजन को वापस लाने को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि नए सीजन में बे (अनन्या के किरदार का नाम) की जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा, लेकिन पहले सीजन वाला ह्यूमर, इमोशन और मस्ती वाला अंदाज बरकरार रहेगा। उन्होंने प्राइम वीडियो के साथ दोबारा जुड़ने पर खुशी जताई और कहा कि 'बे' (अनन्या के किरदार का नाम) और उसके दोस्तों को एक बार फिर हंसी, इमोशन और धमाल से भरे सफर पर ले जाने के लिए वह काफी उत्साहित हैं। नए सीजन के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने कहा, 'सीजन-1 को मिला प्यार और रिस्पॉन्स इस बात का सबूत है कि दर्शकों ने 'बे' (अनन्या के किरदार का नाम) के उतार-चढ़ाव भरे सफर और उसकी बेबाक जिंदगी से गहरा जुड़ाव महसूस किया। सीजन 2 के साथ हम उस दुनिया को और आगे ले जाना चाहते थे, 'बे' के नए पहलुओं को दिखाना चाहते थे, लेकिन वो ह्यूमर, दिल और बिंदास अंदाज बरकरार रखना चाहते थे, जिसे सबने खूब पसंद किया था।' उन्होंने आगे कहा, 'प्राइम वीडियो के साथ दोबारा जुड़कर हम काफी उत्साहित हैं, ताकि दर्शकों को 'बे' की जिंदगी का एक नया चैप्टर दिखा सकें, जहां वो और उसकी प्यारी बहनें हंसी, इमोशन और खूब सारे धमाल से भरे एक और सफर पर निकलेंगी। कोलिन डी'कुन्हा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में अनन्या पांडे लीड रोल में हैं। उनके अलावा इसमें श्रुति हासन इस सीजन से जुड़ रही हैं। इसके साथ ही वीर दास, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा और मिनी माथुर भी अहम किरदारों में दिखेंगे। आठ एपिसोड वाली इस सीरीज को करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्व मेहता ने धर्मैटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। वेब सीरीज 'कॉल मी बे' 17 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर भारत समेत दुनिया के 240 से ज्यादा देशों में स्ट्रीम होगी।

ग्रीस में छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे सैफ-करीना



करीना कपूर खान और सैफ अली खान की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और चर्चित जोड़ियों में से एक है, जो अपनी शानदार केमिस्ट्री, स्टाइल और मजेदार नोकझोंक के लिए जानी जाती है। कपल इन दिनों ग्रीस में अपनी फैमिली ट्रिप इंजॉय कर रहा है। मंगलवार को अभिनेता सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली ट्रिप की कुछ झलकियां फैंस के साथ शेयर कीं, जिसमें कपल सनसेट के सामने रोमांटिक अंदाज में पोज देते हुए एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है। बेबो के साथ कपल की फोटो पोस्ट करते हुए सैफ ने कैप्शन में लिखा, 'सनसेट तो मुख्य आकर्षण होना चाहिए था, लेकिन कोई मेरा ध्यान भटका रहा है।' पहली फोटो में एक्टर खूबसूरत सनसेट के बैकग्राउंड में सड़क पर खड़े नजर आ रहे हैं। सैफ एक साइनबोर्ड के सामने पोज दे रहे हैं, जिस पर 'सनसेट' लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा, 'अगर कोई शक हो तो। सैफ ने जेह की एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वो बस बैठे हुए हैं। नन्हा जेह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा है। फोटो पर उन्होंने लिखा, 'मुझे ये तस्वीर बहुत पसंद है। आत्मचिंतन का एक दुर्लभ पल।' एक्टर ने छुट्टियों के दौरान पढ़ी गई किताबों की एक तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'छुट्टियों में पढ़ाई को भी शानदार बनाए रखा।' इसके बाद सैफ ने बीच पर मैगजीन का लुत्फ उठाती बेबो की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, 'हम दोनों को पढ़ना पसंद है, बस जॉनर अलग-अलग हैं (दरअसल मुझे टैटलर काफी पसंद है)।' इसी के साथ, सैफ ने यह भी बताया कि उन्हें ग्रीस के बारे में क्या-क्या पसंद है। उन्होंने लिखा, 'ग्रीस के बारे में पसंद करने के लिए बहुत कुछ है। छोटी-छोटी खाड़ियां और बीच, क्रिस्टल जैसा



राष्ट्रपति व अन्य ने मुंबई आतंकी हमलों की बरसी पर शहीदों को किया नमन

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने गुरुवार को 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की बरसी पर जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों तथा शहीदों को नमन किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने एक्स पर लिखा, 'हमारे बहादुर सैनिकों, पुलिसकर्मियों तथा उन सभी लोगों के साहस को सलाम है, जो आतंकवाद के खिलाफ निडर होकर खड़े हुए। उनका बलिदान और निस्वार्थ सेवा हमारे देश की आत्मा में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। आतंकवाद भले ही जिंदगियों को तबाह कर दे लेकिन



यह साहस, करुणा और दृढ़ता से एकजुट राष्ट्र के हौसले को कभी नहीं तोड़ सकता। आज, हम पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, और आतंकवाद को हर रूप में खत्म करने तथा एक अधिक शांतिपूर्ण और मानवीय दुनिया की दिशा में काम करने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराते हैं।' उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहनशीलता) की नीति पर अडिग है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद को हराने और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के संकल्प के साथ पूरा देश एकजुट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बहादुर सुरक्षाकर्मियों का अदम्य साहस, कर्तव्य के प्रति समर्पण और मातृभूमि के लिए अटूट निष्ठा हमेशा देश की यादों में अंकित रहेगी। यह दिन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने तथा शांति एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के अपने संकल्प को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। देश उन सभी बहादुर नायकों और निर्दोष नागरिकों के बलिदान को हमेशा कृतज्ञता के साथ याद रखेगा।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के साहस, वीरता और अटूट समर्पण को नमन है, जो आतंकवाद के सामने डटकर खड़े रहे। उनका साहस कर्तव्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। भारत आतंकवाद को उसके सभी रूपों में खत्म करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ सबसे जघन्य अपराध है। आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। आज, भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और आतंकवाद के हर रूप तथा हर साजिश के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि केन्द्र सरकार आतंकवाद के हर रूप से लड़ने और इसमें शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार की नीति 'जीरो टॉलरेंस' (सहन न करने) की है।

न्यूज IN ब्रीफ

नेपाल की कृषि मंत्री गीता चौधरी ने स्कूटर से पहुंचकर मीट कोल्ड स्टोरेज का किया औचक निरीक्षण



काठमांडू। नेपाल की कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने मांस उत्पादों की स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की स्थिति जानने के लिए काठमांडू के बालाजू और सीतापाइला स्थित मीट कोल्ड स्टोरेज का औचक निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि मंत्री चौधरी खुद स्कूटर चलाकर निरीक्षण के लिए पहुंचीं। उनके स्कूटर पर पीछे निजी सुरक्षा अधिकारी बैठे हुए थे। मंत्री चौधरी ललितपुर स्थित जावलाखेल क्वार्टर से स्कूटर चलाकर निकलीं और सबसे पहले बालाजू स्थित वैली कोल्ड स्टोर पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने सीतापाइला स्थित बुढाथोकी कोल्ड स्टोर का भी निरीक्षण किया। उनके सचिवालय की सदस्य सरिता चौधरी ने इसकी जानकारी दी। मंत्री के सचिवालय के अनुसार यह निरीक्षण 17 नवंबर से लागू किए गए 'पशु वधशाला तथा मांस जांच अधिनियम, 2026 के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया। सरकार ने उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काठमांडू घाटी के तीनों जिलों- काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर के सभी स्थानीय निकायों में इस कानून को औपचारिक रूप से लागू किया है। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कोल्ड स्टोरेज में मांस के भंडारण की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों के पालन की जांच की। उन्होंने उपभोक्ताओं के स्वच्छ, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण मांस का उपभोग करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन और निर्धारित मानकों का पालन अनिवार्य बताया। सरकार का कहना है कि इस कानून के प्रभावी कार्यान्वयन से मांस की खरीद, भंडारण और बिक्री की व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाया जा सकेगा।

हिमालयी ग्लेशियर झीलों से बाढ़ का खतरा कम करने के लिए नेपाल, संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की, 5 करोड डॉलर की परियोजना, 3.85 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ



काठमांडू। नेपाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ (ग्लोफ) के खतरे को कम करने और स्थानीय समुदायों की जान-माल की सुरक्षा के लिए करीब 5 करोड डॉलर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। 'ग्लोफ संजीवनी' नाम की इस परियोजना से बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में रहने वाले 3 लाख 85 हजार से अधिक लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। इनमें 55 प्रतिशत महिलाएं होंगी। वहीं, परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली नदी घाटियों के निचले इलाकों में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचेगा। मंगलवार को काठमांडू में आयोजित एक उद्घाटन कार्यशाला में इस परियोजना की औपचारिक शुरूआत की गई। इसमें नेपाल सरकार के अधिकारियों, ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ), यूएनडीपी, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों और विकास साझेदारों ने हिस्सा लिया।

चार खतरनाक ग्लेशियर झीलों का जलस्तर घटाया जाएगा

परियोजना के तहत नेपाल की चार उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का जलस्तर कम किया जाएगा। इनमें मनांग जिले की दोना (थुलागी), संखुवासभा की लोअर बरुण और सोलुखुम्बु जिले की लुमडिंग त्सो तथा होंगु-2 झील शामिल हैं। योजना के अनुसार, दोना, लोअर बरुण और लुमडिंग त्सो झीलों का जलस्तर तीन-तीन मीटर घटाया जाएगा, जबकि होंगु-2 झील का जलस्तर एक मीटर कम किया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए मौसम और जल विज्ञान संबंधी निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार, जलवायु जोखिम से संबंधित सूचना और योजना निर्माण तथा नदी घाटियों में प्राकृतिक उपायों और सुरक्षा संरचनाओं का विकास भी किया जाएगा।

एन चंद्रशेखरन की तीसरी बार नियुक्ति के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा टाटा ट्रस्ट

नई दिल्ली। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और आरडी टाटा ट्रस्ट (आरडीटीटी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में टाटा संस और उसके 6 निदेशकों के खिलाफ गुरुवार को मुकदमे दायर किए हैं। हाई कोर्ट की एकल पीठ शुक्रवार को इन मुकदमों पर सुनवाई कर सकती है। कोर्ट में टाटा ट्रस्ट की ओर से दायर मुकदमों के अनुसार एन. चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त करने के लिए टाटा संस के निदेशक मंडल की 17 सितंबर का पारित प्रस्ताव अमान्य था। ट्रस्ट ने कहा कि इसे कंपनी के अंतर्नियमों (एओए) के अनुच्छेद 121 के तहत जरूरी समर्थन में मत नहीं मिला था। दोनों ट्रस्ट ने एन. चंद्रशेखरन को कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी है। एसडीटीटी ने 50 करोड़ रुपये और आरडीटीटी ने 15 करोड़ रुपये के हजार्ने की मांग की है। दोनों ट्रस्ट ने इस राशि पर सालाना 18 फीसदी ब्याज भी मांगा है। ट्रस्ट ने तत्काल राहत के तौर पर यह मांग की है कि 30 नवंबर को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में नामित निदेशकों के बीच मतभेद की स्थिति में टाटा संस के चेयरमैन अपने निर्णायक मताधिकार का इस्तेमाल न कर सकें। यह विवाद 17 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में चंद्रशेखरन को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन अगले पांच साल के लिए फिर से नियुक्त किए जाने के बाद शुरू हुआ। इससे पहले दोनों ट्रस्ट ने बुधवार रात हाई कोर्ट जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। उनका कहना है कि 17 सितंबर के बाद से इस मामले में भेजे गए पत्रों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नोएल टाटा की अध्यक्षता वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। ट्रस्ट ने 17 सितंबर को पारित निदेशक मंडल के प्रस्ताव को चुनौती दी है। ट्रस्ट ने 20 सितंबर को जारी एक बयान में कहा था कि यह प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं हुआ और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

सोनपुर मेला में लोककला और संगीत की प्रस्तुतियों को दर्शकों ने सराहा

सारण। विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में देर रात्रि तक विभिन्न विभागों की सहभागिता के साथ सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत पर्यटन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा विद्युत विभाग से जुड़ी प्रस्तुतियां और गतिविधियां शामिल रहीं। सारण के कलाकार धीरज राम ने लोकसंगीत और मुजफ्फरपुर की लोकगायिका इंदु बाला शर्मा ने आकर्षक लोकगीतों से दर्शकों को लोकसंस्कृति की परंपरा से जोड़ा। गया की मोहिनी अग्रवाल ने गजल व भजन प्रस्तुत किए। वहीं रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तक नालंदा संगीत परिषद के लोकनृत्य और सबीर की साकार कलाकृति ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर झलक दिखाई। दर्शकों ने तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित यह मेला व्यापार व पर्यटन के साथ-साथ बिहार की लोककला और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का सशक्त मंच बना हुआ है।



प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उनकी ओर से साझा एक संस्कृत सुभाषितम् में इस बात को रेखांकित किया गया है कि विद्वानों द्वारा गहन विचार-विमर्श के बाद बनाई गई नीतियां और सिद्धांत चिरस्थायी होते हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ₹इस पावन अवसर पर संविधान के शिल्पकार बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन एवं वंदन। यह दिन हमारे संविधान निमार्ताओं को श्रद्धांजलि देने और इसमें निहित मूल्यों को मजबूत करने के संकल्प को दोहराने का अवसर है। संविधान निमार्ताओं द्वारा दिया गया यह ग्रंथ भारतीय लोकतंत्र की एक अमूल्य विरासत है। संविधान के आदर्श और मूल्य 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक संस्कृत सुभाषितम भी साझा किया, ₹बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपताः। कथञ्चिन्न विलियन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥₹ जिसका भावार्थ है कि विद्वानों द्वारा अनेक लोगों के साथ मिलकर भली-भाँति विचार और विवेचन कर निर्धारित की गई नीतियाँ किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होतीं।



केंद्रीय गृह सचिव और आईबी निदेशक आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर, करेंगे सुरक्षा हालात की समीक्षा

एजेंसी

जम्मू। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के निदेशक महेश दीक्षित गुरुवार को यहां पहुंच रहे हैं। वे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे और सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हालिया खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सक्रिय लगभग 65 विदेशी आतंकवादियों में से 55 का संबंध पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से



है। अधिकारियों का अनुमान है कि इनमें से लगभग 35 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से, 25 जैश-ए-मोहम्मद से और बाकी अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि 18 नवंबर 2026 को कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में अब कोई भी स्थानीय आतंकवादी सक्रिय नहीं बचा है। सुरक्षाबलों ने दूरदराज के जंगली और पहाड़ी इलाकों में अपने अभियान तेज कर दिए हैं। वे विदेशी आतंकियों का पता लगाने और घुसपैठ रोकने के लिए खुफिया नेटवर्क और निगरानी (सर्विलांस) का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन हालात को देखते हुए आज उच्च-स्तरीय बैठक में शीर्ष खुफिया और सुरक्षा अधिकारी मौजूदा सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा करेंगे।

इस बैठक में समग्र सुरक्षा माहौल, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल और भविष्य की उन रणनीतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है जिनसे संभावित खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और केंद्र शासित प्रदेश में शांति व स्थिरता बनाए रखी जा सके। आईबी निदेशक का पद संभालने के बाद महेश दीक्षित का जम्मू-कश्मीर का यह पहला दौरा है। देश के सबसे वरिष्ठ खुफिया पद पर पहुंचने से पहले वे जम्मू-कश्मीर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर व्यापक और सूक्ष्म दोनों ही स्तरों पर हालात संभालने का उनका लंबा अनुभव उन्हें ऐसी विशेषज्ञता देता है जो केंद्र शासित प्रदेश को आतंकवाद के खतरे से मुक्त करने की भविष्य की रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी।

भाजपा 1 से 25 दिसंबर तक चलाएगी राष्ट्रव्यापी 'सेवा दूत अभियान', घर-घर पहुंचाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में 1 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक 'सेवा दूत अभियान' चलाएगी। 25 दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान का समापन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर होगा। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना तथा पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। सूत्रों के अनुसार इस अभियान के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें भी एकत्र करेंगे, ताकि उन्हें सरकार और पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके।



हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात होंगे सेवा दूत

अभियान के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और चयनित कार्यकर्ताओं को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में 25 दिनों के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन्हें ह्यसेवा दूतह्ण या ह्यविस्तारकह्ण के रूप में तैनात किया जाएगा। ये कार्यकर्ता संबंधित विधानसभा क्षेत्र में रहकर जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करेंगे। सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक सेवा दूत को संगठनात्मक मंडल में लगभग पांच दिन बिताने होंगे। इस दौरान वे गांवों, शहरी वार्डों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों की स्थिति और पार्टी संगठन की मजबूती का आकलन भी करेंगे।

अपने गृह जिले से बाहर मिलेगी जिम्मेदारी

अभियान को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई राज्यों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके गृह जिलों से बाहर के विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी देने की योजना है। जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इससे कार्यकर्ता स्थानीय परिस्थितियों का स्वतंत्र रूप से आकलन कर सकेंगे।

कई राज्यों में तैयारियां शुरू

सेवा दूत अभियान को लेकर बिहार, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में संगठनात्मक कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे आगामी चुनाव वाले राज्यों में भी अभियान की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बांग्लादेश में दो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार, एक पर गोपालगंज हिंसा में शामिल होने का आरोप

एजेंसी

ढाका (बांग्लादेश)। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की खुफिया शाखा ने दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 25वें बैच के अधिकारी मो. अबुल कलाम आजाद और दूसरे 33वें के मो. रकीबुल हसन हैं।

डीएमपी के अतिरिक्त आयुक्त (खुफिया) शफीकुल इस्लाम ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (बांग्लादेश) ने अबुल कलाम आजाद की गिरफ्तारी के लिए अनुरोध भेजा था। प्रोथोम अलो, ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम ने रकीबुल हसन को गिरफ्तार करने के कारणों कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने बताया कि अबुल हसन पर गोपालगंज में हाल ही में हुई हिंसा में शामिल होने का आरोप है। अबुल हसन 'स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन-14' की भैरब कंपनी में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। उनका घर गोपालगंज के मुक्सुदपुर उपजिला के गोविंदपुर में है। रकीबुल हसन भी गोपालगंज के ही रहने वाले हैं।

उधर, भारत में रह रहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश लौटने के इरादे की घोषणा और अवामी लीग के बंद के दौरान हिंसा की आशंका के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि आंतरिक जानकारी लीक करने और हाल ही में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं में मिलीभगत के आरोपों के संबंध में कुछ और पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने बुधवार को सात जिलों में नए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किए। इनमें से पांच जिले अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं। इससे पहले, गोपालगंज सहित ढाका रेंज के 13 जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक रैंक के 12 अधिकारियों को दो महीने के लिए तैनात किया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विभिन्न इकाइयों में नया नेतृत्व लाकर फील्ड स्तर पर पुलिस बल का पुनर्गठन किया जा रहा है। बताया गया है कि गिरफ्तार दोनों पुलिस अधिकारी जुलाई, 2024 के जन-विद्रोह से पहले ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस में तैनात थे। गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस बल के भीतर निगरानी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कुछ अधिकारी ₹फासीवादी ताकतों₹ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में अवामी लीग के फरार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ विदेश में मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों के नाम भी मिले हैं।

हरे निशान पर खुला घरेलू शेयर बाजार

सेंसेक्स 190.36 अंक उछला

एजेंसी

नई दिल्ली। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। शुरूआती कारोबार में बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दिख रही है। सेंसेक्स लगभग 190 अंक और निफ्टी भी 18 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 190.36 यानी 0.23 फीसदी उछलकर 84,128.64 अंक पर कारोबार कर रहा है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) 18.35 अंक यानी 0.071 फीसदी की



बढ़त के साथ 25,837.60 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा है।

बाजार में आज सेक्टोरल मोर्चे पर मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है, जिसमें आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर सबसे ज्यादा बढ़त रही। वहीं, मेटल, रियल्टी, प्राइवेट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में रहे है। सीमेंट, ऑयल एंड गैस, मीडिया, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा, जबकि हेल्थकेयर और फार्मा इंडेक्स सुस्त बने रहे। इसके अलावा रुपया शुरूआती कारोबार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 30 पैसे टूटकर 92.50 प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले बुधवार को सेंसेक्स 1,502.29 अंक यानी 1.82 फीसदी की उछाल के साथ 83,938.28 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 469.60 अंक यानी 1.85 अंकों की बढ़त के साथ 25,819.25 के स्तर पर बंद हुआ था।

हरियाणा के रोहतक में मिलन ढाबे पर चार युवकों की गोली मारकर हत्या

एजेंसी

रोहतक (हरियाणा)। रोहतक के खरावड़ गांव के पास मिलन ढाबे पर देररात चार युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खरावड़ पुलिस चौकी के पास हुए इस हत्याकांड को गैंगवार का नतीजा बताया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक हामिद अख्तर, पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने घटनास्थल का दौराकर हालात का जायजा लिया। सीआईए, स्पेशल सेल और एफएसएल की टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, चारों युवक मिलन ढाबे पर खाना खा रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। मृतकों में तीन युवक झज्जर जिले के गांव डीघल और चौथा युवक बेरी क्षेत्र का रहने वाला है। हत्याकांड को भाऊ और सन्नी रिटोलिया के बीच चल रहे गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले दिनों डीघल में हुई एक युवक की हत्या से भी इस वारदात के तार जुड़े होने की आशंका है।

बड़ी संख्या में ग्रामीण रोहतक पीजीआई पहुंचे हैं। पीजीआई परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। चारों शव पीजीआई पहुंचाए गए हैं। खरावड़ पुलिस चौकी के नजदीक चार युवकों की हत्या ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मंगरा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक रामचंद्र सिंह के पुत्र के विवाह समारोह में हुए शामिल



संवाददाता

बरवाडीह (लातेहार) : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को अपनी धर्मपत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन के साथ लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड अंतर्गत मंगरा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह के पुत्र विजय बहादुर सिंह के वैवाहिक समारोह में शिरकत की।

इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने नवदंपती विजय बहादुर सिंह एवं महिमा को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने नवदंपती के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रेम और खुशहाली बनी रहने की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

विवाह समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक रामचंद्र सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और सगे-संबंधियों से आत्मीय मुलाकात की।

उन्होंने परिवार को इस मांगलिक अवसर पर बधाई दी और स्थानीय लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री के मंगरा पहुंचने पर हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया तथा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय, पलामू क्षेत्र के डीआईजी किशोर कौशल, लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद सहित कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

वरीय अधिकारी जुगनू मिंज में है कला और कलाकार की प्रतिभा

बिनय मिश्रा

झारखंड प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी तथा वर्तमान समय में जामताड़ा जिला में पदस्थापित जुगनू मिंज वरीय झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहने के साथ-साथ कला और संस्कृति में भी जबरदस्त पैठ रखते हैं उनकी प्रशासनिक दक्षता के फलस्वरूप वे काफी लोकप्रिय माने जाते हैं वहीं उनकी कला और प्रतिभा देखते ही बनती है।उनकी प्रतिभा से लोग मंत्रमुग्ध और प्रभावित भी होते हैं। श्री मिंज चक्रधरपुर एवं बंदगांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे वहीं वे चांडिल और हजारीबाग के लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी रह चुके हैं तथा वर्तमान समय में जामताड़ा के वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं।इनकी प्रशासनिक दक्षता और कला को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि दक्षता और योगिता होते हैं एक दूसरे के पूरक



प्रयास से असंभव भी होता है साथ और मिलती है मंजिल

करंट लगने से डॉक्टर की मौत

मुरी : पेशे से डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी की करंट लगने से मौत हो गई। डॉक्टर चौधरी रातू रोड रांची के रहने वाले थे, इनका सामाजिक क्रियाकलाप काफी बढ़ चढ़कर होता था ,समाज में लड़कियों की शादी करना, जरूरतमंदों को जरूर पूरा करना और अपने समाज के लिए भी हर वक्त तैयार भी रहते थे, इसलिए समाज के लोगों ने उनकी मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है।चौधरी समाज के रांची जिला कोषाध्यक्ष भी थे। संवेदना व्यक्त करने वालों में से चौधरी समाज के अध्यक्ष जागो चौधरी एवं दीनू चौधरी समेत कई लोग थे।



रामपुर लैंपस लिमिटेड में विभिन्न पदों के लिए चुनाव संपन्न

संवाददाता

मुरी : सिल्ली प्रखंड अंतर्गत रामपुर लैंपस लिमिटेड में बुधवार 25 नवंबर 2026 को विभिन्न पदों के लिए चुनाव संपन्न हुआ। यह चुनाव 1978 के बाद पहली बार हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए विश्वनाथ माझी ने जीत हासिल की तथा उपाध्यक्ष पद के लिए बुद्धिलाल माझी ने जीत हासिल की। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य में अंबिका देवी, रूपा देवी, मृत्युंजय मंडल, सुधीर प्रसाद साहू , यासीन राय, दयाल चंद्र मांझी, सितुवा माझी शामिल है। मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस बल एवं निर्वाचन कर्मी उपस्थित रहे। मौके पर सभी को बधाई देते हुए स्थानीय मुखिया हरिपद माझी ने कहा कि यह जीत किसानो की जीत है। जो भी कार्य होंगे अब सर्वसम्मति से निर्णय लेकर ही अच्छे ढंग से किया जाएगा।

बड़कागांव से 28 को रवाना होगा सांसद तीर्थ दर्शन का जत्था

संवाददाता

हजारीबाग/बड़कागांव : बुजुर्गों के सम्मान, आस्था और सेवा की अनूठी मिसाल बन चुका हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल का ह्यसांसद तीर्थ दर्शन महाभियानह्ल एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचने जा रहा है। इस महाभियान का 100वां और 101वां जत्था आगामी 28 नवंबर 2026 (शनिवार) को बड़कागांव की धरती से भव्य एवं ऐतिहासिक समारोह के बीच तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगा। इस अवसर पर बड़कागांव क्षेत्र की सांढ़ पंचायत (बड़कागांव मंडल) और नयाटांड़ पंचायत (उरीमारी मंडल) के कुल 130 बुजुर्ग श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों काशी, विंध्याचल, अयोध्या और प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम के दिव्य दर्शन करेंगे।

महाभियान के 100वें जत्थे के प्रस्थान और शतकीय पड़ाव की पूर्णता के अवसर पर बड़कागांव थाना के सामने स्थित मां अम्बे परिसर, गुरुचट्टी में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें भाजपा के कई दिग्गज नेताओं के साथ धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों का जुटान होगा। कार्यक्रम की शुरूआत हवन-पूजन से होगी। इसके बाद तीर्थयात्रियों के पांव पखारकर और उन पर पुष्पवर्षा कर सम्मानपूर्वक विदाई दी जाएगी।

सांसद मनीष जायसवाल की अगुवाई में सभी तीर्थयात्री बड़कागांव चौक होते हुए करीब दो किलोमीटर की पदयात्रा कर सूर्य मंदिर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। इस भव्य पदयात्रा को आकर्षक बनाने के लिए हरे कृष्ण-हरे राम संकीर्तन टोली, टाना भगतों की टोली, विशेष शंखनाद, छऊ नृत्य के कलाकार, ताशा पार्टी और भगवा परिधान में सजे तीर्थयात्रियों की टोली विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।

आयोजन को लेकर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की सभी 83 पंचायतों के गांवों से हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। आयोजकों को उम्मीद है कि जनभागीदारी और धार्मिक उत्साह से यह आयोजन क्षेत्र के लिए यादगार बनेगा।

गांव-गांव पहुंचकर लोगों को दिया जा रहा आमंत्रण : इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए पिछले करीब एक पखवाड़े से सांसद मनीष जायसवाल की टीम और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हैं। कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सांसद प्रतिनिधियों, भाजपा नेताओं और आयोजन से जुड़े स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम स्थल एवं भोजन व्यवस्था के स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह से मुलाकात कर आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और श्रद्धालुओं एवं आम लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके लोकसभा सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र नारायण सिंह, लोकसभा सांसद सह प्रतिनिधि अनिल मिश्रा, लोकसभा सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री जय नारायण प्रसाद, बड़कागांव विधानसभा सांसद प्रतिनिधि पूनम साहू, विधानसभा सांसद मीडिया प्रतिनिधि उमेश दांगी, बड़कागांव मण्डल सांसद प्रतिनिधि रंजीत कुमार, बड़कागांव मंडल अध्यक्ष शिवकुमार शिबू, उरीमारी मंडल अध्यक्ष विजय यादव, बेलतू मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार राज उर्फ शेर सिंह, उदय कुमार, अवध किशोर, सत्यजीत, विद्या अलंकार, दामोदर प्रसाद मेहता, सत्यदेव कुमार, कुंवर महतो, प्रमोद साहू समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहें।

ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

23 पुड़िया ब्राउन शुगर, एक स्विफ्ट डिजायर कार, दो बाइक और चार मोबाइल जब्त

हजारीबाग : जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़कागांव थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 23 पुड़िया में पैक लगभग 11 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से एक स्विफ्ट डिजायर कार, दो मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार, 24 नवंबर 2026 को बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के कदमडीह पुल के पास कुछ युवक ब्राउन शुगर खरीदने-बेचने के लिए आने वाले हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी दल का गठन किया गया।

छापेमारी दल ने सूचना के आधार पर संदिग्ध स्थान की घेराबंदी की। इसी दौरान कुछ युवक कदमडीह पुल के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार एवं मोटरसाइकिल से पहुंचे। पुलिस को देखकर सभी भागने का प्रयास करने लगे। हालांकि, पुलिस ने सशस्त्र बल के सहयोग से मौके पर मौजूद पांच युवकों को पकड़ लिया।

